मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

उत्तरशक्ति

हिन्दी दैनिक

मुंबई
वर्षः 9 अंक 33
शनिवार, 08 अगस्त 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

हर खबर निष्पक्षता के साथ

आवाजें एक साथ उठती हैं तभी सरकार झुकती है: राहुल गांधी

नई दिल्ली, 07 अगस्त। शुक्रवार को प्रयागराज में अपने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तभी झुकती है जब आवाजें एक साथ उठती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि परीक्षा के पेपर लीक होने के खिलाफ छात्रों के लगातार विरोध-प्रदर्शनों ने सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए मजबूर किया। गुरुवार को पर एक पोस्ट में, गांधी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर महीनों तक चले विरोध-प्रदर्शनों के बाद पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ज़िक्र किया और कहा कि सामूहिक कार्रवाई ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया।

गांधी ने कहा कि प्रयागराज वह शहर है जहाँ सबसे ज्यादा युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो गया है। छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है; समस्या उस सिस्टम में है जो उनकी मेहनत की कद्र नहीं करता। उन्होंने नौकरी के उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में पेपर लीक, रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों में लंबी देरी का ज़िक्र किया। कोटा और देहरादून में छात्रों के साथ अपनी हालिया बातचीत का ज़िक्र करते हुए, गांधी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में भी ऐसी ही शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की।

उन्होंने कहा कि आखिरकार, एक मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह सरकार तभी झुकती है जब लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। उन्होंने छात्रों को 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के KP ग्राउंड में होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। KP कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड के इस्तेमाल की मंजूरी वापस लेने के बाद इस कार्यक्रम पर कुछ समय के लिए अनिश्चितता के बादल छा गए थे। मैनेजमेंट ने इसके लिए पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी वजहों और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया था जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

कॉलेज मैनेजमेंट ने शहर की कांग्रेस इकाई को लिखे एक पत्र में आयोजकों से कहा था कि वे बुकिंग रद्द करके जमा की गई रकम वापस ले लें। हालांकि, बाद में प्रशासन ने पहले किए गए रद्दीकरण को वापस लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रयागराज का यह कार्यक्रम परीक्षा की शुचिता, भर्ती में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छात्रों और युवाओं तक पहुंचने की कांग्रेस की कोशिश का हिस्सा है।

Jharkhand JPSC-JSSC विवाद पर सीएम सोरेन बोले- सिस्टम की खामियां दूर करेंगे

रांची, 07 अगस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को रांची में प्रदर्शन कर रहे JPSC और JSSC उम्मीदवारों से मिले। उन्होंने बातचीत के लिए सरकार की तत्परता और छात्रों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जरूरी सुधार लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री ने ये बातें कहीं। सीएम सोरेन ने कहा कि हमने बातचीत का एक तरीका पहले ही तय कर लिया है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार हर छात्र की समस्याओं को समझने के लिए उत्सुक है। अब हम छात्रों की बातों को जयपाल सिंह स्टेडियम की सीमाओं से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

सोरेन ने सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को हल करने के सरकार

के मकसद पर जोर देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसे बड़े और मजबूत सुधारों के साथ आगे बढ़ना है जो छात्रों की उम्मीदों को उनकी जरूरतों के हिसाब से पूरा करें।

विरोध प्रदर्शन के दौरान, JLKM विधायक जयराम महतो ने JPSC प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े एक मामले और JSSC CGL नतीजों से उसके संबंध का हवाला देते हुए चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। महतो ने आरोप लगाया कि यह मांग JPSC प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में है। इस मामले में आरोपी व्यक्ति ने दूसरी रैंक के साथ JSSC CGL परीक्षा पास की थी और उसके परिवार के कई सदस्यों ने भी यह परीक्षा पास की थी। उन्होंने उम्मीदवार के परीक्षा इतिहास की गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि इसलिए, जिन परीक्षाओं में वह शामिल हुआ था, साथ ही संबंधित कंपनी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की भी जांच होनी चाहिए। इस बीच, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा शुक्रवार को रांची में प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुईं। वे राज्य में JPSC, JSSC CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध कर रही थीं।

बारिश में सांसदों की परेशानी होगी दूर, नए संसद भवन के मकर द्वार पर पोर्च बनाने की तैयारी

नई दिल्ली, 07 अगस्त। मानसून सत्र के दौरान लगातार हो रही बारिश के बीच नए संसद भवन में सांसदों और कर्मचारियों को हो रही असुविधा को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने संसद भवन के मकर द्वार पर पोर्च (छायादार प्रवेश संरचना) बनाने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, संसद भवन के आर्किटेक्ट्स और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मकर द्वार पर पोर्च निर्माण की व्यवहार्यता पर चर्चा हुई।

ओम बिरला ने अधिकारियों से कहा कि मकर द्वार पर पोर्च बनाने की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कर जल्द प्रस्ताव तैयार किया जाए। उनका मानना है कि इससे बारिश और खराब मौसम के दौरान सांसदों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को संसद भवन में आने-जाने में सुविधा मिलेगी। दरअसल, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में कई सांसदों को संसद भवन में प्रवेश करते समय बारिश का सामना करना पड़ा।

सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई सांसद छाता लेकर मकर द्वार से संसद में प्रवेश करते दिखाई दिए। पुराने संसद भवन में कुछ प्रमुख प्रवेश द्वारों पर पोर्च की सुविधा उपलब्ध थी, जिससे बारिश और धूप के दौरान लोगों को राहत मिलती थी।

नए संसद भवन के मकर द्वार पर फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से अब पुराने भवन की तर्ज पर यहां भी पोर्च बनाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष ने संबंधित एजेंसियों से तकनीकी और वास्तु संबंधी सभी पहलुओं का आकलन कर व्यवहार्यता रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्माण को लेकर निर्णय लिया जाएगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो मकर द्वार पर पोर्च बनने से संसद भवन में आने वाले सांसदों, अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य अधिकृत विजिटर को बारिश और तेज धूप से राहत मिलेगी।

योगी सरकार ने बुनियादी शिक्षा के एकीकरण को दी नई रफ्तार, 15613 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे परिषदीय विद्यालय परिसरों में स्थानांतरित

लखनऊ, 07 अगस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 15 अगस्त तक 15,613 आंगनबाड़ी केंद्रों को परिषदीय विद्यालय परिसरों में स्थानांतरित करेगी, जिससे बुनियादी शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के एकीकरण को नई गति मिलेगी। ये ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो परिषदीय विद्यालयों से 200 मीटर की परिधि में स्थित होने के बावजूद वर्तमान में गैर-विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं।

मिशन मोड में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को परिषदीय विद्यालय परिसरों में सुरक्षित एवं निर्धारित कक्षा-कक्षों, शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेल के स्थान, बिजली तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण

प्रारंभिक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में 1,89,208 आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें से 1,64,480 केंद्र पहले ही परिषदीय विद्यालय परिसरों से एकीकृत किए जा चुके हैं। इस संबंध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी तथा निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार हर्षिता माथुर ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।

संयुक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार परिषदीय विद्यालयों से 200 मीटर की परिधि में स्थित ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र, जो वर्तमान में गैर-विभागीय भवनों में संचालित हैं, उन्हें संबंधित मैप्ड परिषदीय विद्यालय परिसरों में चरणबद्ध रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण केवल उन्हीं विद्यालयों में किया जाएगा, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के लिए बच्चों हेतु सुरक्षित एवं निर्धारित कक्षा-कक्ष, बिजली तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इस पहल का उद्देश्य तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यालयी वातावरण उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करना है।

माना जा रहा है यह अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थानांतरण के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बुनियादी शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के प्रभावी एकीकरण की व्यापक पहल है। इससे बच्चों को शुरूआती वर्षों से ही बेहतर शैक्षिक वातावरण, विद्यालयी संसाधनों का लाभ और गुणवत्तापूर्ण अधिगम के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही शिक्षा एवं बाल विकास विभागों के बीच समन्वय और संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित परिषदीय विद्यालयों में तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेलने का पर्याप्त स्थान तथा अन्य आवश्यक भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और गतिविधि आधारित शिक्षण वातावरण मिलेगा।

अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत; एक लापता

देहरादून, 07 अगस्त। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में देवप्रयाग-पौड़ी मार्ग पर शुक्रवार को कार खाई में गिरने से एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रतिवादन बल के मुताबिक देवप्रयाग क्षेत्र में हुए हादसे में 16 वर्षीय लड़का घायल हो गया। सूचना मिलते ही देवप्रयाग पुलिस, एसडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया।

एसडीआरएफ ने बताया कि हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का निवासी एक परिवार बोलेरो कार में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी चालक का कार पर से नियंत्रण खो गया और वह गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय वाहन में कुल सात लोग सवार थे। एसडीआरएफ के अनुसार घटनास्थल से एक महिला और बच्ची समेत पांच लोगों के शव बरामद हुए हैं जबकि घायल अवस्था में मिले अरहम नामक लड़के को स्थानीय निवासियों ने अस्पताल भिजवा दिया।

आयुष्मान भारत नियमों के उल्लंघन पर 2,359 अस्पताल पैनल से बाहर, लोकसभा में बोले नड्डा

नयी दिल्ली, 07 अगस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि इस साल 31 मई तक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिशानिदेर्शों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2,000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1,200 अन्य को निलंबित कर दिया है। नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशानिदेर्शों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 328.49 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। नड्डा ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना में

धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि ये स्वचालित प्रणालियां दावा जमा होने के 24 घंटे के भीतर असामान्य दावा पैटर्न की पहचान करती हैं, जिनमें अनधिकृत बिलिंग, दोहरी प्रविष्टि, बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रक्रियाओं और मरीज की पहचान का गलत इस्तेमाल शामिल है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों की भुगतान से पहले जांच की जाती है और धोखाधड़ी वाले दावों का भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे 31 जुलाई, 2026 तक 676.14 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकित्सा उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

TIWARI'S SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
✓ 34+ Years of Academic Excellence
✓ Experienced & Dedicated Faculty
✓ Personal Attention
✓ Printed Notes & Regular Tests
✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055
Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
● Std. XI & XII (Sci.)
● NEET
● JEE (Main & Advance)
● MHT-CET
● Polytechnic & Engg
● Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

ढाका की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों की नई परीक्षा

-ललित गर्ग

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटने की घोषणा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया है। जिस समय बांग्लादेश की राजनीति सत्ता परिवर्तन, वैचारिक ध्रुवीकरण और संस्थागत अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, उसी समय शेख हसीना ने यह घोषणा कर राजनीतिक विमर्श को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। उनका यह कहना कि ह्यगिरफ्तारी, जेल या मृत्यु का भय भी उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकताह्ल, उनके समर्थकों के लिए भावनात्मक आह्वान है तो विरोधियों के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती। बांग्लादेश में पिछले वर्ष सत्ता परिवर्तन के बाद जो राजनीतिक वातावरण बना, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और राजनीतिक सहिष्णुता पर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के विरुद्ध सुनाया गया फैसला और उसके बाद उनके समर्थकों पर बढ़ती कार्रवाइयों ने यह संकेत दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे प्रतिशोध की राजनीति में बदलती जा रही है। हाल ही में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे पूर्व क्रिकेट कप्तान साकिब अल हसन के घर पर हुआ हमला भी इस बात का संकेत है कि राजनीतिक असहमति अब सामाजिक तनाव का रूप लेने लगी है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के एक करीबी सहयोगी द्वारा शेख हसीना को ह्यतुरंत लौटकर सामना करनेह्ल की चुनौती देना बताता है कि बांग्लादेश का राजनीतिक वातावरण अभी भी सामान्य नहीं हुआ है।

लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल या नेता से असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति का समाधान न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया और स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी नेता की लोकप्रियता का उत्तर प्रतिबंध, दमन या भय के वातावरण से दिया जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। शेख हसीना की वापसी को केवल एक व्यक्ति की वापसी के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि अवामी लीग को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश होती है, तो यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा। वास्तविकता यह भी है कि बांग्लादेश की राजनीति आज केवल अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनललिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान, 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत और भविष्य की वैचारिक दिशा का भी बन चुका है। अवामी लीग स्वयं को मुक्ति संग्राम की मूल चेतना का प्रतिनिधि बताती है, जबकि बीएनपी भी अब उसी विरासत पर अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। इतिहास की इस प्रतिस्पर्धी व्याख्या ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा किया है। ऐसी परिस्थितियों में शेख हसीना की वापसी केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बदलेगी, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श की दिशा भी प्रभावित करेगी।

इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, आर्थिक सहयोग और सामरिक हितों पर आधारित हैं। पिछले डेढ़ दशक में दोनों देशों के संबंधों में अभूतपूर्व निकटता आई, जिसका एक बड़ा आधार शेख हसीना सरकार और नई दिल्ली के बीच बना विश्वास था। सीमा विवादों का समाधान, ऊर्जा सहयोग, संपर्क परियोजनाएं, आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई तथा पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन ने इस विश्वास की नई परीक्षा शुरू कर दी है। नई दिल्ली ने एक ओर शेख हसीना को सुरक्षा और आश्रय दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने ढाका की नई सरकार से संवाद भी जारी रखा है। यही परिपक्व कूटनीति का परिचायक है। भारत के सामने चुनौती किसी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ा दिखाई देने की नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश के साथ स्थायी और संतुलित संबंध बनाए रखने की है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला बारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसमें भाग लेते हैं और भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ सकारात्मक संवाद होता है, तो दोनों देशों के बीच हाल के तनावों को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह केवल औपचारिक शिखर बैठक नहीं होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का अवसर भी होगी। भारत को इस मंच का उपयोग केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा सहयोग पर भी स्पष्ट संवाद स्थापित करना चाहिए। भारत के सामने अनेक जटिल प्रश्न भी हैं। गंगा जल संधि के नवीनीकरण, तीस्ता जल बंटवारे, सीमा-पार व्यापार, अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा तथा शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेंगे। इनमें किसी भी विषय पर भावनात्मक या राजनीतिक प्रतिक्रिया के बजाय कानूनी, कूटनीतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। विशेष रूप से प्रत्यर्पण का प्रश्न केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। भारत को अपनी संधियों, न्यायिक प्रक्रियाओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भी नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान सरकार के शुरूआती महीनों में चीन के साथ बढ़ते संपर्क और सामरिक महत्व की परियोजनाओं पर समझौते इस बात का संकेत हैं कि ढाका अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिस्पर्धा की मानसिकता के बजाय विश्वास और विकास की साझेदारी को प्राथमिकता दे। यदि भारत आर्थिक सहयोग, निवेश, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर विकसित करता है, तो दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं।

शेख हसीना की वापसी का प्रश्न अंततः बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र की परीक्षा है। यदि उन्हें निष्पक्ष राजनीतिक अवसर मिलता है, तो जनता स्वयं तय करेगी कि भविष्य का नेतृत्व किसे सौंपना है। लेकिन यदि राजनीतिक प्रतिशोध, दमन और हिंसा का वातावरण बना रहता है, तो इससे न केवल बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख प्रभावित होगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत को इस पूरे घटनाक्रम में संयम, संतुलन और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। न तो उसे किसी आंतरिक राजनीतिक विवाद का पक्षकार बनना चाहिए और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा करनी चाहिए। भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य एक स्थिर, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध पड़ोस होना चाहिए। यही उसकी सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होगी। आज आवश्यकता किसी राजनीतिक विजय की नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता की है। बांग्लादेश को यह सिद्ध करना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं, बल्कि विपक्ष के सम्मान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक सहिष्णुता का भी नाम है। वहीं भारत को यह दिखाना होगा कि वह पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को व्यक्तियों के बजाय संस्थागत विश्वास, पारस्परिक सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ाने में सक्षम है। दिसंबर 2026 में यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं, तो वह केवल एक नेता की वापसी नहीं होगी, वह बांग्लादेश के लोकतंत्र, भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिरता की एक साथ परीक्षा होगी। यदि इस चुनौती को संवाद, लोकतांत्रिक मयार्दा और विवेकपूर्ण कूटनीति के साथ संभाला गया, तो यह संकट दोनों देशों के संबंधों में एक नए विश्वास और नई शुरूआत का आधार भी बन सकता है। यही समय की सबसे बड़ी मांग है। यहां एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि शेख हसीनाा के बांग्लादेश यानी वतन-वापसी से वहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को नई धार मिलेगी या फिर वह और अधिक बंट जाएंगी?

बदलता संघ और बदलता युवा: संघ प्रमुख मोहन भागवत का 'जेन-जी' के नाम संदेश

अशोक भाटिया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परंपरा, अनुशासन और प्राचीन मूल्यों को सर्वोपरि रखने के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत समकालीन युवा पीढ़ी—जिन्हें 'जेन-जी' और 'जेन-अल्फा' कहा जाता है—के पक्ष में खुलकर खड़े होते हैं, तो यह भारतीय विमर्श में एक युगांतरकारी मोड़ का संकेत है। हाल ही में संघ प्रमुख ने जिस बेबाकी और संवेदनशीलता के साथ युवाओं की सोच, उनके अधिकारों, उनके विरोध प्रदर्शनों और उनकी देशभक्ति का समर्थन किया है, उसने देश के नीति-निमार्ताओं और पुरानी पीढ़ी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। यह संदेश दशार्ता है कि संघ समय के साथ न केवल बदल रहा है, बल्कि नए भारत की नई सोच को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। डिजिटल बदलावों और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच यह संदेश राष्ट्र निर्माण की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

अमूमन हर दौर में पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से शिकायतें रही हैं। आज भी अक्सर 'जेन-जी' को लेकर यह धारणा बनाई जाती है कि वे रील्स और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में खोए हुए हैं, वे एकाग्रता की कमी से जूझ रहे हैं और अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। लेकिन डॉ. मोहन भागवत ने इन तमाम रूढ़िवादिता को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज की युवा पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार, पारदर्शी, जागरूक और देशभक्त है।

संघ प्रमुख का यह कहना कि वे ₹नई पीढ़ी पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं,₹ एक बहुत बड़ा वक्तव्य है। यह भरोसा इस समझ से उपजा है कि आज का युवा पाखंड को पसंद नहीं करता। वह जो सोचता है, वही बोलता है; उसकी कथनी और करनी में दिखावा नहीं होता। उनकी देशभक्ति किसी प्रदर्शनकारी राष्ट्रवाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश को आंतरिक रूप से मजबूत और अधिक न्यायसंगत बनाने की उनकी स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है। जब देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन युवाओं की इस प्रामाणिकता को मान्यता देता है, तो यह युवाओं के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देता है और पुरानी पीढ़ी के संशय को दूर करता है।

इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाला हिस्सा वह था, जहां डॉ. भागवत ने युवाओं के विरोध प्रदर्शनों और उनके अधिकारों की बात की। पिछले कुछ वर्षों में देश ने विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर छात्रों के उग्र आंदोलन देखे हैं। दुर्भाग्यवश, कई बार ऐसे आंदोलनों को फौरन दबाने या उन्हें 'देश-विरोधी' या 'गुमराह' बताने की कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन सरसंघचालक ने इस पर बेहद परिपक्व और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण रखा।

उन्होंने साफ किया कि व्यवस्था, सरकारी नीतियों या किसी घटना के खिलाफ आवाज उठाना और विरोध प्रदर्शन करना युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकार है। युवाओं का गुस्सा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुधारने, पारदर्शी बनाने और अधिक जवाबदेह देखने के लिए होता है। किसी आंदोलन में शामिल होने मात्र से कोई युवा देश-विरोधी नहीं हो जाता। यह बयान उन ताकतों के लिए एक कड़ा सबक है जो हर असहमति की आवाज को दबा देना चाहती हैं। लोकतंत्र की असली ताकत निरंतर संवाद में है, दमन में नहीं, और युवाओं का विरोध इसी स्वस्थ संवाद की मांग करता है।

आज का युवा सूचना क्रांति के उस दौर में जी रहा है जहां दुनिया भर का ज्ञान उसकी उंगलियों पर है। वह किसी भी बात या परंपरा को सिर्फ इसलिए चुपचाप नहीं मान लेता क्योंकि वह किसी बुजुर्ग या प्राचीन व्यवस्था ने कही है। वह तर्क चाहता है, वह प्रमाण चाहता है, वह न्यायसंगत कारण चाहता है। डॉ. मोहन भागवत ने युवाओं के इस खोजी स्वभाव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की खुलकर सराहना की है। उन्होंने माना कि आज की पीढ़ी बिना डरे सीधे सवाल पूछता है और पुरानी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे इन सवालों से भागने या नाराज होने के बजाय उनके तार्किक और संतोषजनक जवाब दें।

यह दृष्टिकोण संघ की पारंपरिक छवि से अलग और प्रगतिशील है। संघ प्रमुख का यह मानना कि समस्याओं या असंतोष का समाधान 'बल' या 'उपेक्षा' से नहीं हो सकता, आज के समय की सबसे बड़ी नीतिगत जरूरत है। जब छात्र किसी नीति पर अपनी चिंताएं जताते हैं, तो प्रशासन या समाज को उनके साथ एक 'मेंटर' की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि किसी क्रूर शासक की तरह। उनके तर्कों को संवेदनशीलता से सुनना और उनकी आशंकाओं को दूर करना ही उनके असंतोष को शांत करने का एकमात्र सर्वमान्य उपाय है।

आज का भारतीय समाज वैचारिक रूप से अत्यधिक ध्रुवीकृत है। दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि मध्यमार्ग गायब सा दिखता है। ऐसे माहौल में संघ प्रमुख का यह बयान एक पुल का काम करता है। यह संदेश उन युवाओं तक भी एक सकारात्मक प्रतिध्वनि के रूप में पहुंचता है जो संघ को हमेशा एक अत्यंत पुरातनपंथी संस्था के रूप में देखते आए हैं। जब वे देखते हैं कि संघ का सर्वोच्च नेता उनके विरोध करने के अधिकार और उनकी तार्किकता का सम्मान कर रहा है, तो वैचारिक कट्टरता की दीवारें कमजोर होती हैं। यह लेख इस बुनियादी सत्य को रेखांकित करता है कि राष्ट्र निर्माण किसी एक विचारधारा के एकाधिकार से नहीं हो सकता। इसके लिए देश के हर युवा की ऊर्जा, उसकी स्वतंत्र सोच और उसके रचनात्मक विरोध की आवश्यकता है। संघ प्रमुख ने युवाओं को यह अहसास कराया है कि वे देश के भविष्य ही नहीं, बल्कि वर्तमान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं और राष्ट्र को उनके सहयोग की जरूरत है। डॉ. भागवत का यह वक्तव्य जितना युवाओं के लिए मार्गदर्शक है, उससे कहीं अधिक यह देश की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस तंत्र और राजनीतिक दलों के लिए एक गंभीर 'चेतावनी' की तरह है। पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्रों की मांगों को जिस तरह बलपूर्वक दबाया गया, संघ प्रमुख का यह बयान उन प्रशासनिक नीतियों पर एक परोक्ष प्रहार है। यदि प्रशासनिक तंत्र युवाओं को केवल एक 'कानून-व्यवस्था' की समस्या के रूप में देखता रहेगा, तो हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। विश्वविद्यालयों को पुलिस छावनी बनाने के बजाय उन्हें स्वतंत्र विचार-विमर्श का केंद्र बनाना होगा। जब तक युवाओं को यह विश्वास नहीं होगा कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जा रहा है, तब तक सड़कों का असंतोष पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। प्रशासन को अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़कर युवाओं के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा। डॉ. मोहन भागवत का यह संदेश केवल 'जेन-जी' के लिए प्रेरणा नहीं है, बल्कि पुरानी पीढ़ी, राजनीतिक दलों और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है। हमें युवाओं को एक समस्या के रूप में देखना बंद करना होगा; वे वास्तव में देश की समस्याओं का सबसे आधुनिक समाधान हैं। युवा आबादी की ऊर्जा को दबाने के बजाय उसे सही दिशा देना ही समझदारी है।

यदि भारत को सचमुच एक वैश्विक शक्ति, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और 'विश्वगुरु' बनना है, तो हमें अपनी युवा आबादी की इस ऊर्जा, उनकी बेबाकी और उनकी तार्किकता को सहेजना होगा। संघ प्रमुख ने इस दिशा में संवाद का हाथ बढ़ाकर एक बड़ी पहल की है। अब वास्तविक जिम्मेदारी सरकार, शिक्षण संस्थानों और परिवारों की है कि वे युवाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। 'जेन-जी' पर किया गया यह भरोसा ही आने वाले कल के समृद्ध, सशक्त, समावेशी और लोकतांत्रिक भारत की नींव बनेगा।

रजिस्ट्री कार्यालय बनेगा संपत्ति सुरक्षा का प्रहरी! फर्जी दस्तावेजों पर कैसेगा शिकांजा

-सुरेश गांधी

उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीयन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ रही है। विधानसभा में पारित नए विधायी प्रावधानों के बाद स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को रजिस्ट्री कराने आने वाले व्यक्ति के मालिकाना हक का सत्यापन करने का अधिकार मिलने जा रहा है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक सुधार भर नहीं, बल्कि संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी और फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन राज्यमंत्री रविन्द्र जायसवाल के अनुसार अब तक पंजीयन विभाग मुख्य रूप से दस्तावेजों की औपचारिक जांच और स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति पर केंद्रित था। सामान्य धारणा यह रही कि संपत्ति खरीदने वाला स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि बेचने वाला वास्तविक मालिक है या नहीं। इसी व्यवस्था की कमजोरियों का लाभ उठाकर कई मामलों में दूसरे की संपत्ति बेच देने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और विवादित भूमि का हस्तांतरण करने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं।

पुरानी व्यवस्था की प्रमुख सीमाएं

अब तक की व्यवस्था में रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने दो पक्ष उपस्थित होते थे और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते थे। यदि दस्तावेज औपचारिक रूप से पूर्ण होते और निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा हो जाता, तो पंजीयन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी। विभाग के पास यह जांच करने का स्पष्ट अधिकार नहीं था कि संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में उसी संपत्ति का स्वामी है या नहीं। परिणामस्वरूप कई विवाद बाद में अदालतों तक पहुंचते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि संपत्ति संबंधी मुकदमों का एक बड़ा कारण मालिकाना हक को लेकर उत्पन्न विवाद हैं। कई मामलों में वास्तविक स्वामी को तब जानकारी मिलती थी जब भूमि का कब्जा बदलने लगता था या न्यायालय में वाद दायर हो जाता था।

नया प्रावधान क्या बदलेगा

नए प्रावधान लागू होने के बाद पंजीयन विभाग दस्तावेजों के साथ-साथ मालिकाना स्थिति का भी परीक्षण कर सकेगा। संभावित रूप से निम्न बिंदुओं की जांच पर जोर रहेगा:

.राजस्व अभिलेखों में दर्ज स्वामी का नाम
उत्तराधिकार या वसीयत से जुड़े दस्तावेज
पूर्व विक्रय विलेखों की श्रृंखला
सहमति या अधिकार से संबंधित प्रमाण
विवाद या न्यायालयीन रोक की स्थिति

यदि जांच के दौरान गंभीर विसंगति पाई जाती है, तो पंजीयन रोका जा सकेगा और संबंधित पक्षों से अतिरिक्त प्रमाण मांगे जा सकेंगे।

फजीर्वाड़े पर कैसे लगेगी रोक

मान लीजिए किसी व्यक्ति की भूमि को कोई दूसरा व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का प्रयास करता है। पुरानी व्यवस्था में यदि दस्तावेज सतही रूप से सही दिखाई देते, तो पंजीयन हो जाने की आशंका रहती थी। बाद में वास्तविक मालिक को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर ही मालिकाना स्थिति की जांच होने से ऐसे मामलों के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सरकारी भूमि, ट्रस्ट की संपत्ति, विवादित भूखंड या उत्तराधिकार विवाद वाली संपत्तियों के मामलों में भी अतिरिक्त सावधानी बरती जा सकेगी।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को मिलेंगे नए अधिकार, संपत्ति धोखाधड़ी रोकने की दिशा में बड़ा कदम. उत्तर प्रदेश की पंजीयन व्यवस्था में होने जा रहा बदलाव केवल एक प्रशासनिक संशोधन नहीं, बल्कि संपत्ति सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब तक रजिस्ट्री प्रक्रिया मुख्य रूप से दस्तावेजों और स्टाम्प शुल्क तक सीमित थी, लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था में वास्तविक मालिकाना हक के सत्यापन पर जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री, दूसरे की भूमि बेचने, विवादित संपत्तियों के हस्तांतरण और सरकारी जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी रोक लग सकेगी। डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेज सत्यापन और विभागीय जांच की नई प्रणाली से खरीददारों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह व्यवस्था पारदर्शी और तकनीक आधारित ढंग से लागू हुई तो प्रदेश में संपत्ति लेनदेन अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और विवादमुक्त बन सकता है। यह बदलाव आम नागरिकों की जीवनभर की कमाई और संपत्ति अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है..

आम नागरिक को क्या लाभ

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ संपत्ति खरीदने वाले नागरिकों को मिल सकता है। यदि पंजीयन कार्यालय स्तर पर प्रारंभिक सत्यापन हो जाता है, तो खरीददार का जोखिम कम होगा। इससे निम्न लाभ संभावित हैं:

सुरक्षित संपत्ति लेनदेन
मुकदमों की संख्या में कमी
बैंक ऋण प्रक्रिया में भरोसा बढ़ना
संपत्ति बाजार में पारदर्शिता
निवेशकों का विश्वास मजबूत होना

हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि नागरिकों को स्वयं जांच-पड़ताल से पूरी तरह मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। कानूनी सलाह और दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता बनी रहेगी।

क्या प्रक्रिया लंबी हो जाएगी

सुधारों के साथ यह चिंता भी उठ रही है कि अतिरिक्त सत्यापन से पंजीयन प्रक्रिया में समय बढ़ सकता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार का प्रयास है कि तकनीक आधारित सत्यापन अपनाकर प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न होने दिया जाए। डिजिटल अभिलेखों का उपयोग, ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलान और दस्तावेज सत्यापन की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस दिशा में सहायक हो सकती है। यदि अधिकांश राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे तो जांच अपेक्षाकृत तेजी से पूरी की जा सकेगी।

तकनीक की बढ़ती भूमिका

प्रदेश में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर पहले से काम चल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पंजीयन व्यवस्था का भविष्य राजस्व अभिलेख, भूलेख, नगर निकाय रिकॉर्ड और न्यायालयीन जानकारी के डिजिटल एकीकरण में है। यदि विभिन्न विभागों के डेटाबेस आपस में जुड़े हों, तो किसी संपत्ति की स्थिति का त्वरित सत्यापन संभव हो सकेगा। ई-पंजीयन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, दस्तावेज अपलोड और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं पहले ही कई स्थानों पर लागू हैं। नया सत्यापन तंत्र इन्हीं प्रयासों का अगला चरण माना जा रहा है।

चुनौतियां भी कम नहीं

सुधार लागू करने में कई व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं:

पुराने अभिलेखों में त्रुटियां
नामांतरण लंबित होना
संयुक्त स्वामित्व के विवाद
ग्रामीण क्षेत्रों में अपूर्ण रिकॉर्ड
अलग-अलग विभागों के रिकॉर्ड में अंतर

यदि रिकॉर्ड स्वयं स्पष्ट नहीं होंगे तो सत्यापन प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ रिकॉर्ड शुद्धिकरण अभियान को भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं।

कानूनी दृष्टि से महत्व

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार पंजीयन कार्यालय द्वारा किया जाने वाला सत्यापन अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि एक प्रशासनिक जांच होगी। स्वामित्व विवाद का अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। फिर भी प्रारंभिक जांच से संदिग्ध लेनदेन की पहचान संभव होगी और विवादित संपत्तियों के हस्तांतरण को कठिन बनाया जा सकेगा।

राजस्व और बाजार पर प्रभाव

पारदर्शी पंजीयन व्यवस्था से संपत्ति बाजार में विश्वास बढ़ सकता है। जब खरीददार को लगेगा कि दस्तावेजों की सरकारी स्तर पर जांच हुई है, तो लेनदेन अधिक सुरक्षित महसूस होगा। इससे वैध बाजार को बढ़ावा मिलने और फर्जी लेनदेन पर अंकुश लगने की संभावना है। राजस्व विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता बढ़ने से दीर्घकाल में वैध पंजीकरण बढ़ सकते हैं और सरकार के राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

जनजागरूकता की जरूरत

नई व्यवस्था सफल तभी होगी जब नागरिक अपने दस्तावेज समय पर अपडेट कराएं। नामांतरण, उत्तराधिकार प्रविष्टि, खाता संशोधन और राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करना प्रत्येक संपत्ति स्वामी की जिम्मेदारी है। अधूरे रिकॉर्ड भविष्य में परेशानी का कारण बन सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित नई पंजीयन व्यवस्था संपत्ति सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में सामने आ रही है। यदि मालिकाना सत्यापन प्रभावी ढंग से लागू हुआ, रिकॉर्ड डिजिटलीकरण तेज हुआ और प्रक्रियाएं पारदर्शी रहीं, तो फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। यह सुधार केवल सरकारी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास नहीं, बल्कि नागरिकों की जीवनभर की कमाई और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा कदम है। आने वाले महीनों में नियमावली, प्रक्रिया और तकनीकी ढांचे के स्पष्ट होने के बाद इस व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि प्रदेश की पंजीयन प्रणाली एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, जहां केवल स्टाम्प शुल्क ही नहीं, बल्कि वास्तविक मालिकाना हक भी केंद्र में होगा।

तीन राज्यों के उपचुनाव नतीजों ने भाजपा को दिया बड़ा राजनीतिक संदेश

तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बिहार की बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हराकर 64,151 वोट हासिल किए। भाजपा उम्मीदवार को 44,827 वोट मिले जबकि राजद की रेखा कुमारी महज 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर सिमट गईं। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि 1995 से लगातार भाजपा के कब्जे वाली सीट का पतन है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर भाजपा ने परिवार के बाहर उम्मीदवार उतारकर जो जोखिम लिया, वह भारी पड़ गया।बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34.30 फीसदी रहा, जो पिछले विधानसभा चुनाव के 41.45 फीसदी से सात अंक कम है। करीब 3.8 लाख मतदाताओं में से बहुत कम लोग वोट डालने पहुंचे। फिर भी जो पहुंचे, उन्होंने साफ संदेश दिया। प्रशांत किशोर ने इसे विधायक चुनने का चुनाव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक संदेश पहुंचाने वाला जनमत संग्रह बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अपनी राय रखी है। जीत के बाद उन्होंने साफ कहा कि बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाने का वादा करने वाली पार्टी ने उसी दौर के चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। यह हार भाजपा के लिए इसलिए भी चुभने वाली है क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला उपचुनाव था। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद एनडीए का सामाजिक संतुलन बिगड़ गया था। अति पिछड़ा और महिला मतदाताओं के बीच नीतीश का जनाधार हमेशा मजबूत रहा। सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता बांकीपुर जैसे शहरी, प्रबुद्ध और मध्यमवर्गीय इलाके में उतनी नहीं बन पाई। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने कानून व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े किए। सवर्ण और शहरी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो गया। नीट पेपर लीक और उच्च शिक्षण संस्थानों के नियमों को लेकर युवाओं में आक्रोश भी चुनावी माहौल में घुला। भाजपा ने उम्मीदवार भी बदला। पहले अमित कुमार उर्फ बंटी को टिकट दिया, फिर परिवारिक कारणों से उन्होंने नाम वापस ले लिया और नीरज कुमार को उतारा। यह फेरबदल भी पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी भाजपा को झटका लगा। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 66,757 वोट हासिल कर भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराया। आशुतोष को 60,741 वोट मिले। यह सीट कांग्रेस के राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई थी। भारती को बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन साल की सजा हुई थी। 2023 में भारती ने नरोत्तम मिश्रा को सात हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। मिश्रा तीन बार जीत चुके थे। उनकी नाराजगी और स्थानीय संगठन की सुस्ती ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेताओं के प्रचार के बावजूद नतीजा नहीं बदला। दतिया में मतदान 71.44 फीसदी रहा, जो बांकीपुर से कहीं ज्यादा था। कांग्रेस ने अपनी सीट बचाई और भाजपा को सत्ताधारी होने के बावजूद हार का स्वाद चखना पड़ा।

-अजय कुमार

गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा ने राहत की सांस ली। सतेंद्रभाई पटेल ने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को करीब 30,500 वोटों से हराया। पटेल को 55,481 वोट मिले जबकि रबारी को 24,851। लेकिन जीत का अंतर पहले के मुकाबले काफी कम रहा। 2022 में भाजपा ने लगभग एक लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। मतदान प्रतिशत 37 फीसदी के आसपास रहा। योगेश पटेल की मौत के बाद हुई इस उपचुनाव में भाजपा ने सीट तो बचा ली लेकिन विपक्ष की बढ़त साफ दिखी।उपचुनाव हमेशा बड़ी लहर का संकेत नहीं होते। 2018 में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर भाजपा हारी थी। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की सीटें थीं। समाजवादी पार्टी ने इसे बड़ी जीत बताई लेकिन 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। महाराष्ट्र के कस्बा पेठ में 2023 में भाजपा हारी लेकिन 2024 विधानसभा में एनडीए ने 232 सीटें जीतकर वापसी की। बिहार में भी 1994 में लवली आनंद की वैशाली उपचुनाव जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने का दावा किया गया था लेकिन बाद में पार्टी विलय करना पड़ा। बांकीपुर में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा। ऐसे में इसे सीधे पूरे राज्य या केंद्र की राजनीति से जोड़ना जल्दबाजी होगी।

फिर भी बांकीपुर का नतीजा अलग है। प्रशांत किशोर की जन सुराज 2025 विधानसभा चुनाव में 238 उम्मीदवार उतारकर बुरी तरह हारी थी। ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई थी। अब पहली जीत भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में हुई है। उन्होंने राजद को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। तेजस्वी यादव के लिए भी यह चिंता का विषय है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रशांत किशोर को कौवे की मिसाल देकर नसीहत दी कि डाल टूटने से पेड़ नहीं गिरता। लेकिन वोट ट्रांसफर के संकेत साफ हैं। शहरी मतदाता भाजपा और राजद दोनों के पुराने ढर्रे से ऊब चुके थे। प्रशांत किशोर ने तीसरा विकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर वोट भाजपा के पारंपरिक समर्थकों के थे जिन्होंने अहंकार के खिलाफ मतदान किया।भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का जादू भी इस बार कमजोर पड़ा। गैर यादव ओबीसी, अति पिछड़ा और सवर्ण वोट बैंक का गठजोड़ हमेशा काम आता रहा लेकिन बांकीपुर में युवा और मध्यम वर्ग की नाराजगी भारी पड़ी। कोर वोट बैंक का एक हिस्सा उत्साहपूर्वक मतदान केंद्र नहीं पहुंचा। रविशंकर प्रसाद के कथित बयान को लेकर भी नैरेटिव बना। प्रशांत किशोर ने इसे स्वाभिमान से जोड़कर माहौल बना लिया। भाजपा समय रहते इसे बेअसर नहीं कर पाई। अब सवाल यह है कि यह झटका स्थायी है या अस्थायी। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे विपक्ष का चेहरा नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की बात करने वालों का चेहरा बनेंगे। उन्होंने घूसखोरी खत्म करने, सरकारी स्कूल सुधारने और क्षेत्र के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने का वादा किया। सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी और जनता के फैसले का सम्मान किया। गिरिराज सिंह ने विपक्ष को ज्यादा खुश न होने की सलाह दी और 2009 के उदाहरण दिए जब उपचुनाव में हार के बाद भी बड़ा चुनाव जीता गया।तीनों नतीजे एक साथ देखें तो साफ है कि अब चुनाव सिर्फ पुराने वोट बैंक या बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं जीते जा सकते। उम्मीदवार की स्वीकार्यता, स्थानीय मुद्दे, संगठन की एकजुटता और जमीनी काम ज्यादा मायने रखते हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पदयात्राएं, बूथ प्रबंधन और युवाओं के बीच पैठ ने जीत की पटकथा लिखी। भाजपा के फैसलों ने भी उनका रास्ता आसान किया। दतिया में उम्मीदवार चयन की गलती और गुजरात में कम होता अंतर यही बताते हैं कि चुनौतियां बढ़ रही हैं।आचार्य चाणक्य कहते थे कि राजनीति में एक पराजय कई विजयों से ज्यादा शिक्षा देती है। बांकीपुर की हार भाजपा के लिए आत्ममंथन का मौका है। सोशल इंजीनियरिंग के अलावा नेतृत्व, संगठन और संदेश तीनों स्तरों पर नए समीकरण बनाने होंगे। प्रशांत किशोर की यह पहली चुनावी जीत बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत खड़ी करने का संकेत है या सिर्फ एक स्थानीय नतीजा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तीन दशक पुराना किला ढह चुका है और संदेश साफ है।

पडघा या अंबाडी अप्पर तहसील कार्यालय का विवाद गहराया, अंबाडी के समर्थन में 30 हजार आपत्तियां दर्ज

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी तालुका में प्रस्तावित अप्पर तहसील कार्यालय के मुख्यालय को लेकर पडघा और अंबाडी के बीच विवाद तेज हो गया है। अंबाडी तालुका कृती समिती ने दावा किया है कि अंबाडी को मुख्यालय बनाए जाने के समर्थन में 30 हजार आपत्तियां एवं सुझाव उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में जमा कराए गए हैं। समिति के समन्वयक मोहन पाटील ने बताया कि पहले सरकार ने पडघा में अप्पर तहसील कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसका अंबाडी क्षेत्र में विरोध हुआ। इसके बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद सरकार ने नई प्रक्रिया शुरू करते हुए पडघा और अंबाडी दोनों विकल्पों पर फिर से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए। समिति के अनुसार, पहले भी सैकड़ों आपत्तियां, 45 ग्रामसभाओं के प्रस्ताव, 37 आदिवासी ग्राम पंचायतों के समर्थन, 9 विधायकों, 2 सांसदों तथा गो. बा. पिंगुलकर समिति की सिफारिशें अंबाडी के पक्ष में दी गई थीं। अब जनजागरण अभियान के बाद 30 हजार से अधिक आपत्तियां जमा कराई गई हैं। कृती समिति के अध्यक्ष शरद पाटिल ने कहा कि अंबाडी 125 गांवों का प्राकृतिक केंद्र है और आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण इसे मुख्यालय बनाकर स्वतंत्र तालुका घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंबाडी को स्वतंत्र तालुका बनाए जाने की मांग पिछले 30 वर्षों से लंबित है, जबकि पडघा को मुख्यालय बनाने की कोई प्रमुख मांग पहले नहीं थी। उनका आरोप है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विवाद खड़ा हुआ, जिससे अब पडघा और अंबाडी के स्थानीय लोग आमने-सामने आ गए हैं।

वाणगांव में 10 अगस्त को मेगा रोजगार मेला का आयोजन, 22 कंपनियों में मिलेगी नौकरी का मौका

पालघर(उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र शासन के कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग की पहल पर पालघर जिले के युवाओं के लिए सोमवार 10 अगस्त 2026 को वाणगांव में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में 22 प्रतिष्ठित कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी। जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र की सहायक आयुक्त रेणुका तम्मलवार ने जिले के अधिक से अधिक युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 में पूरे महाराष्ट्र में 1,000 रोजगार मेले और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। इसी अभियान के तहत पालघर जिले में इस वर्ष 22 रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा। वाणगांव का यह रोजगार मेला उसी श्रृंखला का महत्वपूर्ण आयोजन है। रोजगार मेला सोमवार 10 अगस्त 2026 को पद्मश्री जीव्या सोमा माशे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई), चिंचणी रोड, वाणगांव, तहसील डहाणू में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस मेले में 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा तथा स्नातक शिक्षित युवक-युवतियां भाग ले सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न कंपनियों में उपलब्ध रिक्त पदों पर रोजगार का अवसर मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को महास्वयम पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले पंजीकरण नहीं कराया है, वे पहले अपना पंजीकरण कर जॉब सीकर लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करें। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जॉब फेयर विकल्प में पालघर जिले का चयन कर रोजगार मेला (2026-27) पालघर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को रोजगार मेले में बायोडाटा, पासपोर्ट आकार फोटो, आधार कार्ड, सेवायोजन पंजीकरण कार्ड, बैंक खाते का विवरण, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाणपत्रों की मूल एवं छायाप्रतियां साथ लानी होंगी। साथ ही बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेजों की कम से कम पांच प्रतियां भी अपने साथ रखना आवश्यक होगा। सहायक आयुक्त रेणुका तम्मलवार ने कहा कि जिले और राज्य के युवाओं के लिए यह रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से समय पर उपस्थित होकर रोजगार मेले का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।अधिक जानकारी के लिए जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र, पालघर के दूरभाष 02525-299812 पर संपर्क किया जा सकता है।

सैटरडे ही नहीं सातों दिन चलेगी लैब, घर जाएं कामचोर अफसर, तुकाराम मुंढे का अल्टीमेटम

मुंबई। महाराष्ट्र में अपनी दबंग अंदाज से हड़कंप मचाए अन्न और औषध प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने साफ कर दिया है कि सैटरडे ही नहीं जरूरत पड़ने पर लैब सातों दिन चलेंगी। मुंढे का यह आदेश उस घटनाक्रम के बाद आया है जब छत्रपति संभाजीनगर के 29 एफडीए अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्रोह करते हुए आरोप लगाया था कि वे ज्यादा काम करवातो हैं और छुट्टी भी नहीं देते हैं। वीक ऑफ वाले दिन भी काम करना पड़ता है। इन अधिकारी और कर्मचारियों ने विभाग के मंत्री नरहरि झिरवाल को शिकायत की थी। मुंढे ने अब एफडीए में अफसरों और कर्मचारियों की क्लास लगाते हुए स्टैंड साफ कर दिया है।

तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र में मिलावट खोरों पर शिकंजा कसने के साथ के साथ होटल-रेस्टोरेंट और दूसरे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बहाली में जुटे हैं। मुंढे ने स्कूल और उसके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड को भी प्रतिबंधित कर दिया है। मुंढे ने नियमों का पालन न करने वाले 29 कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे सरकारी नियमों के अनुसार काम नहीं कर सकते तो घर चले जाएं। मुंढे ने कहा है कि जिन्हें शासन के नियमों के अनुसार काम करना मंजूर नहीं है, वे इस्तीफा देकर जा सकते हैं। छत्रपति संभाजीनगर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन की प्रयोगशाला के 29 अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुंढे को कार्यशैली को लेकर विभागीय मंत्री नरहरि झिरवाल से शिकायत की है। यह ज्ञापन 15 जुलाई को सौंपा गया था। इसमें कहा गया है कि दो शिफ्ट में काम कराने, शनिवार-रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी ड्यूटी लगाई गई। रिक्त पदों के कारण बढ़ते कार्यभार काफी ज्यादा है। ऐसे में नमूनों की जांच की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ज्ञापन पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी हैं।

कजरी महोत्सव में झूमी मीरा रोड, लोकगीतों की गूंज से सराबोर हुआ माहौल

सिने कलाकार सुषमा को मिला 'स्त्री शक्ति सम्मान', भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा एवं अभियान संस्था के संयुक्त आयोजन में उमड़ी महिलाओं की भीड़

मीरा रोड (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा एवं अभियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भव्य कजरी महोत्सव का आयोजन मीरा रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध कजरी गायिका संजोली पाण्डेय एवं पार्श्व गायिका योगिता मिश्र ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से समूचे वातावरण को लोक संस्कृति के रंग में रंग दिया। संजोली पाण्डेय ने अपने लोकप्रिय कजरी गीत ₹पिया मेहंदी लियाई द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना...₹ की प्रस्तुति देकर उपस्थित महिलाओं और दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने झूले का आनंद लिया, हाथों में मेहंदी रचाई और पारंपरिक सावन उत्सव का भरपूर आनंद उठाया।

मुख्य अतिथि एवं मीरा-भायंदर के भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि कार्यक्रम में माताओं-बहनों और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि हमारी पारंपरिक संस्कृति और लोक परंपराएं आज भी जीवंत हैं। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य करते हैं।

मीरा-भायंदर महानगरपालिका की महापौर श्रीमती डिम्पल विनोद मेहता ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा

कि महिलाओं की सामाजिक एवं सांस्कृतिक भागीदारी समाज की प्रगति का आधार है। इस अवसर पर सिने कलाकार सुषमा को समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन, मनपा सभापति हसमुख गहलोत, सभागृह नेता एड. रवि व्यास, नगरसेवक मदन उदितनारायण सिंह, मनोज रामनारायण दुबे, श्रीप्रकाश सिंह, पंकज पांडेय (दरोगा), नगरसेविका श्रीमती स्नेहा शैलेश पांडेय, अशोक तिवारी, विवेक उपाध्याय, बृजेश तिवारी, ज्ञानेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष संतोष दीक्षित, महामंत्री महेंद्र पाण्डेय, राज पाठक, सूर्यदेव सक्सेना, के.डी. प्रजापति, रामअवतार एवं आशीष दुबे ने शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया।

कार्यक्रम के अंत में उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष संतोष दीक्षित ने सभी अतिथियों, कलाकारों एवं उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से उत्तर भारतीय लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा।

नशा मुक्त भारत अभियान को मिलेगा जन-जन का साथ, 18 अगस्त को 5 लाख लोग लेंगे भाग

पालघर(उत्तरशक्ति)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पालघर जिले में 18 अगस्त 2026 को व्यापक जनजागरूकता अभियान आयोजित किया जायेगा। जिलाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड़ तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे के मार्गदर्शन में जिला परिषद पालघर के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान का संचालन किया जायेगा। अभियान में जिले के लगभग 5 लाख नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी एवं विद्यार्थी भाग लेंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखना, नशाग्रस्त लोगों को नशामुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना तथा शराब, धूम्रपान और मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना है। इसके तहत जिले के स्कूलों, महाविद्यालयों, शासकीय कार्यालयों, ग्राम पंचायतों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में जनजागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं, व्याख्यान, परामर्श सत्र तथा अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षित स्वयंसेवक विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देने के साथ ही साथ स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन ई-प्लेज लेकर नशामुक्ति का संकल्प लें, अपने क्षेत्र में जनजागरूकता फैलायें तथा नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण कर इस सामाजिक अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से आवाहन किया है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर नशामुक्त, स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

वतमाल जिले के झरी जामड़ी तालुका के आदिवासी विद्यार्थियों के मिड - डे मील योजना पर अनाज के संकट को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग

मुंबई (उत्तरशक्ति)। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से आदिवासी दिवस का आयोजन किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ यवतमाल जिले के आदिवासी बाहुल इलाके झरी जामणी तहसील में संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मिड-डे मील) योजना अनाज की कमी के कारण गंभीर संकट से जूझ रही है। राज्य स्तर से खाद्यान्न की आपूर्ति समय पर नहीं होने के कारण कई सरकारी स्कूलों में केवल तीन से चार दिनों का ही अनाज बचा है। यदि जल्द आपूर्ति नहीं हुई तो हजारों विद्यार्थियों के सामने दोपहर के भोजन का संकट खड़ा हो सकता है। जिसके कारण मुंबई और नवी मुंबई आदिवासी पारधी महासंघ के अध्यक्ष संतोष एकनाथ पवार ने महाराष्ट्र सरकार से आदिवासी विद्यार्थियों के लिए

अनाज के संकट को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है।

बता दें कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के अधिकांश बच्चों के लिए मिड-डे मील केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि दिन का सबसे पौष्टिक भोजन होता है। ऐसे में खाद्यान्न की आपूर्ति रुकने से स्कूल प्रशासन चिंता में है। कई स्कूल शेष बचे स्टॉक के सहारे योजना चला रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अनाज भेजकर व्यवस्था बनाए रखी जा रही है।

मिड-डे मील योजना में अनाज की भारी कमी: कहीं-कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उधार अनाज लेकर भोजन तैयार किया जा रहा है, तो कुछ गांवों में जनसहयोग से योजना जारी रखने का प्रयास हो रहा है। वर्ष 1995 से संचालित यह योजना विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने, कुपोषण कम करने और ड्रॉपआउट रोकने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। वहीं आदिवासी पारधी समाज मुंबई व नवी मुंबई महासंघ के अध्यक्ष संतोष एकनाथ पवार का कहना है कि खाद्यान्न आपूर्ति में आई बाधा ने इस योजना की निरंतरता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला स्तर से कई बार मांग भेजे जाने के बावजूद राज्य स्तर से पर्याप्त अनाज उपलब्ध नहीं हो सका है, जिससे स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। संतोष एकनाथ पवार ने महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग के मंत्री नरहरी झिरवाल से मांग की है कि आदिवासी विद्यार्थियों के मिड- डे मील योजना पर अनाज के संकट को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें।

चेंबूर में दो लाइसेंस होल्डर गटई कामगारों के स्टाल हटा दिए जाने से आक्रोश

चेंबूर (उत्तरशक्ति)। मनपा की हिटलर शाही इतनी बढ़ गई है कि वे लायसेंस धारी स्टाल वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जिसका तरोताजा उदाहरण चेंबूर में देखने को मिला है। बताया जाता है कि चेंबूर परिसर में परवानाधारक गटई कामगार श्रीमती अनुसया भगवान डिडोले और श्रीमती चंद्रभागा अन्ना अहिरे का स्टाल कई सालों से है। उक्त दोनों ही महिलाओं के स्टाल गत दिनों बगैर किसी पूर्व सूचना और स्थाई व्यवस्था के सामान के साथ हटा दिया गया। जिसके कारण इन लायसेंस धारी महिलाओं के स्टाल हटा दिए जाने से गटई कामगारों में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना की सूचना मिलते ही चर्मकार विकास संघ मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष मराठे

के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने एम पश्चिम विभाग के सहायक आयुक्त शंकर भोसले से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिष्टमंडल ने मनपा की ओर से की गई कथित अनधिकृत कार्यवाही पर सहायक आयुक्त से इसका जवाब मांगा और तीव्र नाराजगी जताई। शिष्टमंडल द्वारा किए गए प्रश्नों को सहायक आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए एक महीने के भीतर स्थाई व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया। इस शिष्टमंडल में प्रमुख रूप से समाजसेविका सुश्री अनीता पटोले, गणेश डिडोले, महेश अहिरे, श्रीमती चंद्रभागा अहिरे, मोहन डिडोले सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। उक्त जानकारी गटई कामगार आघाड़ी मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष अशोक कांबले ने दी है।

राहुल एजुकेशन ने किया AGI के चेयरमैन डॉ. हरिशचंद्र मिश्रा का सम्मान

मुंबई (उत्तरशक्ति)। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राहुल एजुकेशन द्वारा आज आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन तथा फाउंडर ट्रस्टी डॉ हरिश्चंद्र मिश्रा के 75 वें वर्ष में प्रवेश करने पर उनका सम्मान किया गया। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे ने राहुल एजुकेशन के चेयरमैन पंडित लल्लन तिवारी की तरफ से शॉल और स्मृति चिन्ह से उनका सम्मान किया। शिक्षा के क्षेत्र में आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाता है। मुंबई महानगरपालिका से अभियंता पद से सेवानिवृत्त हरिश्चंद्र मिश्रा ने वर्ष 2011 में बोरीवली पश्चिम स्थित सिंपोली परिसर में आदित्य ग्रुप ऑफ

इंस्टीट्यूट्स का शुभारंभ किया। 2005 से ही उन्होंने यहां काम शुरू कर दिया था। पूरी तरह से इमारत बन जाने के बाद उन्होंने शिक्षण संस्थान शुरू किया। मैनेजमेंट कोर्स से शुरू शिक्षण संस्थान ने अबतक विकास और उपलब्धियों की कई ऊंचाइयां तय की है। आज यहां पीजीडीएम, एमबीए, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, अप्लाइड आर्ट्स, बिल्डर्स, एमसीए, एमबीए के पाठ्यक्रम पूरी सफलता और लोकप्रियता के साथ संचालित किया जा रहे हैं। शिक्षण संस्थान को यूजीसी से ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया है, जिसे आधी यूनिवर्सिटी का स्वरूप माना जाता है। समीपवर्ती मेट्रो स्टेशन का कॉलेज के नाम पर आदित्य कॉलेज सिंपोली स्टेशन रखा गया है। नामउनके दोनों युवा सुपुत्र आशीष और आदित्य उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील स्थित मल्हूपुर (देवग्राम) की माटी में पैदा हुए डॉ हरिश्चंद्र मिश्रा ने शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी का जो इतिहास लिखा है, वह सदियों तक याद किया जाता रहेगा।

रोटरी क्लब द्वारा यू. एस. ओस्तवाल इंग्लिश अकादमी में ज्ञान व नवाचार के द्वारा युवा प्रतिभाओं का सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। रोटरी क्लब ऑफ बोईसर-तारापुर के तत्वावधान में गुरुवार को बोईसर स्थित यू. एस. ओस्तवाल इंग्लिश अकादमी में ₹ज्ञान और नवाचार के द्वारा युवा प्रतिभाओं का सशक्तिकरण₹ विषय पर एक प्रेरणादायी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 250 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यशाला के मुख्य वक्ता रोटरी क्लब ऑफ पालघर के पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन निनाद सावे ने विद्यार्थियों को ज्ञान, नवाचार, रचनात्मक सोच तथा आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में सफलता के लिए निरंतर सीखना, कौशल विकास करना तथा नवाचार को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने सरल एवं प्रेरक ढंग से उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्या मनप्रीत सोहेल द्वारा अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते हुए किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में विद्यार्थियों के लिए केवल पुस्तक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नवाचार, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मक सोच एवं तकनीकी दक्षता का विकास भी समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने रोटरी क्लब द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु इस प्रकार की उपयोगी कार्यशालाओं के आयोजन की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ बोईसर-तारापुर के प्रेसिडेंट डॉ. प्रवीण वैश्य, फर्स्ट लेडी अर्चना वैश्य, तत्कालीन अध्यक्ष राम नारायण गोयल, क्लब सेक्रेटरी रेखेश जैन तथा इंटरेक्ट कोऑर्डिनेटर रोटेरियन अलका जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे।कार्यशाला के सफल आयोजन में विद्यालय की इंटरेक्ट क्लब कोऑर्डिनेटर श्रद्धा संखे एवं रोटेरियन अलका जैन का विशेष योगदान रहा। अंत में क्लब सेक्रेटरी रेखेश जैन ने सभी अतिथियों, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट डॉ. प्रवीण वैश्य ने भविष्य में भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार की प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक कार्यशालाओं का नियमित आयोजन करते रहने का विश्वास दिलाया।

टोरेंट पावर फ्रेंचाइजी के विरोध में भिवंडीकर न्याय मंच ने बजाया बिगुल, 31 अगस्त से अनिश्चितकालीन चक्रीय भूख हड़ताल

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडीकर न्याय मंच ने वर्ष 2027 में समाप्त होने जा रही टोरेंट पावर की फ्रेंचाइजी व्यवस्था के विरोध में टोरंट गो बैक आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी है। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 31 अगस्त 2026 से उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, भिवंडी के समक्ष अनिश्चितकालीन चक्रीय भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। शुक्रवार को सनौबर हॉल में आयोजित पत्रकार परिषद में मंच के संयोजक शादाब उस्मानी ने बताया कि वर्ष 2007 में महाराष्ट्र शासन ने भिवंडी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत वितरण व्यवस्था टोरेंट पावर लिमिटेड को फ्रेंचाइजी के रूप में सौंपी थी, जिसका दूसरा कार्यकाल जनवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई शहरों में जनविरोध के बाद फ्रेंचाइजी व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन भिवंडी में लगातार विरोध के बावजूद इसे जारी रखा गया है।

उस्मानी ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ते बिजली शुल्क, कथित फास्ट मीटर, झूठे विजिलेंस मामलों और कंपनी के कथित मनमाने रवैये से पावरलूम उद्योग के साथ-साथ मध्यमवर्गीय एवं गरीब उपभोक्ता भी परेशान हैं। भिवंडीकर न्याय मंच ने मांग की है कि वर्ष 2027 में मौजूदा फ्रेंचाइजी व्यवस्था समाप्त कर पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नई सक्षम निजी विद्युत वितरण कंपनी की नियुक्ति की जाए। साथ ही नई निविदा जारी करने से पहले जनसुनवाई कर नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाएं। मंच ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और निजी कंपनियों की प्रभावी निगरानी के लिए भिवंडी में MERC तथा महावितरण (MSEDCL) के नोडल कार्यालय स्थापित करने की भी मांग की है।शादाब उस्मानी ने कहा कि प्रस्तावित आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संचालित किया जाएगा। इस पत्रकार परिषद में सुरेश राजिव्या तोटे, हमजा सिद्दीकी, जाहिद मुख़्तार, फरीद खान, शादाब खान एवं हमीद शेख आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय:
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामी: शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली तार बेचने का आरोप, छापेमारी में 23 बंडल बरामद

ओबरा,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। ओबरा स्थानीय थाना क्षेत्र के गजराज नगर डाला मोड़ स्थित महामाया इंटरप्राइजेज नामक दुकान पर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली विद्युत तार बेचने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर ओबरा पुलिस और हैवेल्स कंपनी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कार्रवाई की।

बताया गया कि गुरुवार रात कंपनी की शिकायत पर पुलिस टीम ने दुकान की जांच की। जांच के दौरान हैवेल्स कंपनी के नाम से बेचे जा रहे 23 बंडल संदिग्ध (नकली) तार बरामद किए गए। आरोप है कि ग्राहकों को असली के दाम पर नकली सामान बेचा जा रहा था।

हैवेल्स कंपनी के फील्ड ऑफिसर दीप सिंह ने बताया कि कंपनी को काफी समय से नकली तार बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों की जांच के लिए उन्हें भेजा गया था। ओबरा पुलिस के साथ की गई छापेमारी में दुकान से 23 बंडल नकली तार बरामद हुए।

इस मामले में ओबरा पुलिस ने फील्ड ऑफिसर दीप सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान ओबरा थाने के एसआई विनोद यादव, सिपाही संतोष पटेल, अनिल गुप्ता सहित पुलिस टीम मौजूद रही।

प्राथमिक विद्यालय से सिलेंडर चोरी करने वाले दो बाल अपचारी पकड़े गए, चोरी का सिलेंडर बरामद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बदलापुर थाना पुलिस ने प्राथमिक विद्यालय से सिलेंडर चोरी करने के मामले में दो बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया एक इंडेन कंपनी का सिलेंडर बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बदलापुर के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।

थाना बदलापुर में दर्ज मुकदमा संख्या से संबंधित धारा-305 बीएनएस के मामले में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालय लेदुका से आने वाले लिंक रोड के पास से दोनों बाल अपचारियों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी का एक इंडेन कंपनी का सिलेंडर बरामद हुआ। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक शिवाजी सिंह, कांस्टेबल अनिल यादव और कांस्टेबल अजय कुमार थाना बदलापुर शामिल रहे। पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।

सीलिंग के बाद फिर चालू हुआ क्लीनिक?

केराकत में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत स्थित एक निजी पॉली क्लिनिक को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जिस दुर्गावती पॉली क्लिनिक पर पहले प्रशासनिक कार्रवाई और सीलिंग हुई थी, वहां दोबारा इलाज किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

मीडिया टीम के मौके पर पहुंचने पर अस्पताल परिसर में डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। रिपोर्ट के अनुसार, वहां नर्सिंग स्टाफ कार्य करता दिखाई दिया। वहीं भर्ती काउंटर पर मौजूद कर्मचारी ने क्लिनिक के पहले सील होने की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। मामले ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि पहले क्लिनिक पर कार्रवाई हुई थी तो दोबारा संचालन किस आदेश या अनुमति के आधार पर शुरू हुआ? क्या स्वास्थ्य विभाग ने पुनः निरीक्षण कर आवश्यक मानकों की जांच की? क्या यहां उपचार के लिए आने वाले मरीजों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (उटर) से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

यदि लगाए जा रहे आरोप सही पाए जाते हैं तो यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला होगा और निष्पक्ष जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। वहीं यदि आरोप निराधार हैं तो स्वास्थ्य विभाग को भी तथ्यात्मक स्थिति सार्वजनिक कर भ्रम दूर करना चाहिए। फिलहाल पूरा मामला जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में है।

जगतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने नशे के खिलाफ बुलंद की आवाज

जागरूकता रैली निकाल दिया 'नशामुक्त युवा भारत' का संदेश

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के जगतपुर महाविद्यालय, जगतपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने शुक्रवार, 7 अगस्त को नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। महाविद्यालय परिसर से शुरू हुई रैली जगतपुर और रोहनिया क्षेत्र से होते हुए वापस परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। छात्र-छात्राओं ने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए युवाओं से नशामुक्त समाज और नशामुक्त युवा भारत के निर्माण में आगे आने की अपील की। अभियान के साथ महाविद्यालय में पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवानाः जागरूकता रैली का शुभारंभ महाविद्यालय परिसर से हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो.अनिल प्रताप सिंह ने हरी झंडी

दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को स्वयं अनुशासित रहने और समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।

प्राचार्य ने कहा कि नशा मुक्ति की शुरूआत सबसे पहले अपने घर से करनी चाहिए। इसके बाद अपने आस-पड़ोस और समाज के लोगों को भी नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि समाज में नशे की प्रवृत्ति दिखाई देने पर वे चुप न रहें, बल्कि लोगों को इसके दुष्परिणाम समझाएं और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें।

कोतवाली चौराहे पर ई-रिक्शा चालकों में मारपीट, यातायात पुलिस ने संभाला मोर्चा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर कोतवाली क्षेत्र के व्यस्त कोतवाली चौराहे पर शुक्रवार को सवारी बैठाने को लेकर तीन ई-रिक्शा चालकों के

बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हनुमान मंदिर के पास सवारी बैठाने को लेकर ई-रिक्शा चालकों में विवाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने पर तीनों चालक आपस में भिड़ गए। इस दौरान चौराहे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई।

सूचना मिलते ही चौराहे पर तैनात पिकेट पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने सभी चालकों को अलग कर मामला शांत कराया और यातायात व्यवस्था को सुचारु कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोतवाली चौराहा शहर के प्रमुख और सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल है। यहां अक्सर ई-रिक्शा चालकों द्वारा सड़क पर ही वाहन खड़ा कर सवारी बैठाने से जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार चालकों के बीच विवाद की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि ई-रिक्शा संचालन के लिए निर्धारित स्टैंड की व्यवस्था की जाए और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि जाम और विवाद की घटनाओं पर रोक लग सके।

'विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा' का संदेश

मेडिकल कॉलेज जौनपुर में नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में नशा मुक्ति जनजागरण पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो. (डॉ.) आर.बी. कमल के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. (डॉ.) ए.ए. जाफरी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश देना रहा।

कार्यक्रम का संचालन तंबाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी डॉ. अनिल कुमार एवं मनोचिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. विनोद वर्मा के समन्वय में किया गया। इस दौरान श्विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवाश् थीम पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एलाइड एवं हेल्थकेयर (पैरामेडिकल) विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक रहा। विद्यार्थियों ने अपने प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही यह संदेश दिया कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज—तीनों के लिए घातक है तथा नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

नाटक में यह भी दर्शाया गया कि साथियों के दबाव, व्यस्त जीवनशैली और जागरूकता की कमी के कारण युवा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। हालांकि समय रहते सही मार्गदर्शन, परामर्श और दृढ़ संकल्प के जरिए नशे से बचा जा सकता है। प्रस्तुति ने मरीजों, तीमारदारों और आमजन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया।

समापन अवसर पर प्राचार्य प्रो. (डॉ.) आर.बी. कमल ने नशा मुक्ति जनजागरण पखवाड़ा के सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारियों, चिकित्सा शिक्षकों, पैरामेडिकल विद्यार्थियों एवं सभी कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को नशामुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

भदोही से भटक कर वाराणसी आये बच्चों को चेतगंज पुलिस नें परिजनों से संपर्क कर सकुशल किया सुपुर्द

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में कल शाम को दो बच्चे जिसका उम्र करीब 09.वर्ष. व दूसरे की उम्र करीब 11. वर्ष.जो एक-दूसरे के पड़ोस के रहने वाले रहें अपने घर से बिना बताये भटककर वाराणसी आ गये थे जो आन्ध्रापुल के पास घूम रहे थे जिसको एक व्यक्ति द्वारा आन्ध्रापुल से अपने साथ थाना चेतगंज पर लाया जिनको थाने पर बैठाकर पूछताछ करने पर अपना नाम पता बताये जिसके माध्यम से थाना भदोही जनपद भदोही की पुलिस से संपर्क कर बच्चो के परिजनों को सूचना कराया गया था जिसके उपरान्त उनके परिजन आज थाना चेतगंज आये उक्त दोनो नाबालिक बच्चों को सुबह

उनके परिजनों को सकुशल सुपुर्द कर किया गया। परिजनों नें थाना चेतगंज पुलिस को धन्यवाद करते हुए कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की प्रशंसा की सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम मे थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला.चौकी प्रभारी तेलियाबाग अली अतहर.उप निरीक्षक संदीप चौरसिया.कांस्टेबल सारिका सिंह शामिल रही।

खुटहन क्षेत्र के रामपुर में नाली विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो पक्षों में लाठी-डंडे चले

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खुटहन थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में नाली निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरी वारदात को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जबकि पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

केराकत में मछली पकड़ने गए कक्षा 9 के छात्र की नदी में डूबने से मौत, परिवार में कोहराम

जितेन्द्र कन्नौजिया

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत क्षेत्र के पसेवा गांव में नदी में डूबने से 13 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान आदर्श कुमार के रूप में हुई है, जो कक्षा 9 का छात्र था।

बताया जा रहा है कि आदर्श कुमार बृहस्पतिवार को गांव के पास नदी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान नदी किनारे उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से छात्र के शव को नदी से बाहर निकलवाया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हृदयविदारक हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बरसठी पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित युवक-युवती को दबोचा, पायल बरामद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बरसठी थाना पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चोरी के मामले में वांछित एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक-एक सफेद धातु की पायल बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। थाना बरसठी में दर्ज मुकदमा संख्या 325/2026, धारा 305, 352, 351(3), 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त आनन्द गौतम पुत्र राहुल कुमार गौतम और अभियुक्ता प्रतिभा गौतम उर्फ अजोरा पुत्री अखिलेश कुमार गौतम, निवासी ग्राम जयरामपुर थाना बरसठी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के पास से चोरी की गई एक-एक पायल बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अम्ब्रीश कुमार सिंह, आरक्षी नीरज कुमार पाल, आरक्षी विपिन शर्मा, महिला आरक्षी रानी और महिला आरक्षी बबिता शामिल रहीं।

शाहगंज में मारपीट के मामले में वांछित किन्नर गिरफ्तार

ईंट से हमला कर साथी को घायल करने का आरोप

शाहगंज,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शाहगंज कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित चल रहे एक किन्नर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर ईंट से हमला कर एक किन्नर को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत शुक्रवार को थाना शाहगंज पुलिस टीम ने सुबह करीब 10:30 बजे वांछित आरोपी गुलाबो किन्नर निवासी डिहवा भादी, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया। मामले के अनुसार 6 अगस्त को डाली किन्नर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह अपने गुरु शमा किन्नर, सीमा किन्नर, बिजली किन्नर और अन्य साथियों के साथ गुलाबो किन्नर के घर बातचीत करने पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान गुलाबो किन्नर ने घर का दरवाजा बंद कर छत पर चढ़कर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी तथा ऊपर से ईंट फेंककर हमला कर दिया। इस

हमले में सीला किन्नर के सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी शाहगंज ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने डाली किन्नर की तहरीर के आधार पर थाना शाहगंज में मुकदमा संख्या 278/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 131, 352, 351(3), 109(1) और 110 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह और उप निरीक्षक ओम प्रकाश पांडेय थाना शाहगंज शामिल रहे।

भूमि विवाद में अपहरण के बाद हत्या का आरोप, नहर से मिला युवक का शव

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के थलोई (हरनहनिया) गांव निवासी 49 वर्षीय अशोक कुमार पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के पुत्र ने भूमि विवाद के चलते साजिश रचकर अपहरण के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार, अशोक कुमार पटेल बीते एक अगस्त को सुबह करीब आठ बजे अपनी स्प्लेंडर बाइक से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को महाराजगंज थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव स्थित नहर से एक क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान अशोक कुमार पटेल के रूप में हुई।

शव मिलने की जानकारी पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मछलीशहर

कोतवाली पहुंच गए। सूचना पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीण शांत हुए।

मृतक के पुत्र आकाश कुमार पटेल ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उनका परिवार और पड़ोसियों के बीच भूमि विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद के चलते विपक्षियों ने साजिश रचकर उनके पिता की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने ईश्वर लाल, उनकी पत्नी फूलकली, पुत्र अंकित, अमरेंद्र पटेल, कविता सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मछलीशहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनीत राय ने बताया कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

हर ग्राम पंचायत में दिखेगी विकास की तस्वीर, मुख्य प्रवेश द्वार पर लगेगा सूचना बोर्ड

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी ग्राम पंचायतों के मुख्य प्रवेश द्वार पर ग्राम सूचना बोर्ड लगाए जाएं, ताकि ग्रामीणों और आगंतुकों को गांव की आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। बोर्ड पर गांव की जनसंख्या, मतदाताओं की संख्या, ग्राम प्रधान का नाम, भू-जल की स्थिति, प्रमुख उपलब्धियां और विलेज सिटीजन चार्टर अंकित किया जाएगा।

कैम्प कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एमडीएम शेड, अमृत सरोवर, तालाब, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा।

बैठक में मनरेगा के तहत सक्रिय जॉब कार्ड धारकों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी, ग्राम पंचायतों में नियमित मास्टर रोल जारी करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के

निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने अमृत सरोवरों को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश देते हुए वहां ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, ट्री गार्ड, लाइटिंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करने को कहा। साथ ही सभी नए सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए फ्लैग पोल स्थापित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विकास कार्यों का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य करने, प्रत्येक कार्य की डिजिटल डायरी तैयार करने, खंड विकास अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण करने तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में फॉगिंग मशीन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, डीसी मनरेगा, सभी खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जौनपुर के विनीत यादव ने ऑल इंडिया पुलिस जूडो चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले के होनहार खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल विनीत कुमार यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर जौनपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस जूडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया। विनीत कुमार यादव मूल रूप से जौनपुर के थाना लाइन बाजार क्षेत्र के ग्राम परियांवा (सहिजाद नगर) के निवासी हैं। खेल के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही रही है। इससे पहले वह वुशू खेल के एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने जूडो में अपनी प्रतिभा को निखारा और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतकर अपनी मेहनत का परिचय दिया। विनीत की इस उपलब्धि से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग और उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों, शुभचिंतकों और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।

विज्ञान संकाय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के विज्ञान संकाय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के स्वागत एवं मार्गदर्शन हेतु इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं मानव आनुवंशिकी विशेषज्ञ प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे रहे।

प्रो. चौबे ने अपने प्रेरक व्याख्यान में भारत की जनसंख्या के इतिहास, मानव प्रवासन, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता तथा जीनोमिक्स के माध्यम से प्राचीन इतिहास को समझने की वैज्ञानिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को शोध, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. प्रदीप कुमार ने की। उन्होंने विज्ञान संकाय की शैक्षणिक उपलब्धियों, आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान

सुविधाओं की जानकारी दी। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने छात्रवृत्तियों एवं छात्र सुविधाओं, जबकि मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रो. अविनाश डी. पाथर्डिकर ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं एवं अनुशासन संबंधी जानकारी साझा की।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. राधिका ने किया। इस अवसर पर प्रो. राम नारायण, डॉ. एस.पी. तिवारी, डॉ. विवेक पांडे, डॉ. संजीव कुमार मौर्य सहित विज्ञान संकाय के शिक्षक उपस्थित रहे। अंत में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी बताते हुए इसे अपने विश्वविद्यालय जीवन की सफल शुरूआत के लिए उपयोगी बताया।

अलखनाथ मंदिर में नाथ कॉरिडोर योजना के तहत विकास कार्यों का निरीक्षण, डीएम ने दिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश

बरेली (उत्तरशक्ति)। नाथ कॉरिडोर योजना के अंतर्गत अलखनाथ मंदिर के पर्यटन विकास कार्यों का शुक्रवार को मंडलीय समिति के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत 1167.04 लाख रुपये की धनराशि से मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें मल्टीपरपज हॉल, वैदिक लाइब्रेरी, 5 फूलों की दुकानें, मुख्य प्रवेश द्वार, ओपन थिएटर तथा मेन गेट से मंदिर तक सड़क निर्माण शामिल हैं।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य को तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं। नाथ कॉरिडोर योजना के तहत हो रहे इन विकास कार्यों से अलखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

करेंट लगने से 5 साल बच्ची की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम

कलीम सिद्दीकी

सरायख्वाजा, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सरायख्वाजा स्थानीय थाना क्षेत्र मे गुरुवार को पंखे की करंट लगने से 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलस गयी। परिजन बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गये जहां चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया। इस घटना से घर में कोहराम मच गया। बता दें कि पतहना गांव निवासी सुरेंद्र गौतम की पुत्री सान्वी गौतम 5 वर्ष पंखे की करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन और पड़ोसी लोगों ने बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गये जहां चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया परिजन बिना पुलिस की सूचना दिये ही बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिये।

एक देश-एक पत्रकार पहचान का मुद्दा भी मुख्यमंत्री तक पहुँचा,स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। काशी के पत्रकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, आवासीय सुविधा तथा पत्रकार सुरक्षा तंत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बुधवार को पत्रकार सुरेश गांधी ने प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विस्तृत मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह तथा पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में वाराणसी के पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने, विशेष पत्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड योजना लागू करने, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मानजनक पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके अतिरिक्त पत्रकार आवास योजना को प्राथमिकता से लागू करने और पत्रकारिता की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का मुद्दा भी रखा गया।

जौनपुर में उर्वरक दुकानों पर प्रशासन का छापा, 42 प्रतिष्ठानों की जांच, 2 लाइसेंस निलंबित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने और नकली व अमानक उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जनपदभर में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 42 उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर, बिक्री अभिलेख, लाइसेंस, मूल्य सूची और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। उर्वरकों की गुणवत्ता परखने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों से 8 नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में अनियमितताएं मिलने पर 5 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितताओं के चलते 2 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली, अमानक अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत उर्वरकों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कृषि विभाग को नियमित और आकस्मिक निरीक्षण अभियान लगातार चलाने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदें, पक्का बिल अवश्य लें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल कृषि विभाग या जिला प्रशासन को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई की जा सके।

सत्ता में आने के बाद गड्ढों पर इअशक्ष की चुप्पी क्यों? भाजपा महामंत्री मनोज बारोट का सवाल

वसई-विरार। वसई-विरार महानगरपालिका की सत्ता में वापसी के बाद शहर की खराब सड़कों और गड्ढों के मुद्दे पर बहुजन विकास आघाड़ी (BAVIA) के रुख को लेकर भाजपा वसई-विरार जिला महामंत्री मनोज बारोट ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए BAVIA ने सड़कों की बदहाली और गड्ढों को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आक्रामक आंदोलन किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसी मुद्दे पर उसकी चुप्पी समझ से परे है। बारोट ने कहा कि 5 अक्टूबर 2025 को पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर के नेतृत्व में BAVIA ने शहर की खराब सड़कों, जानलेवा गड्ढों, सड़क मरम्मत, टेंडर प्रक्रिया और नगर निगम के वित्तीय लेन-देन को लेकर विरोध मार्च निकाला था। उस समय BAVIA नेताओं ने प्रशासन और तत्कालीन व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब जनवरी 2026 में नगर निगम की सत्ता दोबारा BAVIA के हाथ में आने के बाद जनता जानना चाहती है कि उन आरोपों पर क्या कार्रवाई हुई।

उन्होंने सवाल किया कि यदि विपक्ष में रहते हुए BAVIA को प्रशासन के प्रस्तावों, टेंडरों, ठेकों, सड़क निर्माण की गुणवत्ता और खर्चों पर आपत्ति थी, तो सत्ता में आने के बाद इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर सच्चाई जनता के सामने क्यों नहीं रखी जा रही है।

व्हाइट पेपर पर भी मांगा जवाब

भाजपा की ओर से प्रशासनिक काल के प्रस्तावों और वित्तीय फैसलों की जांच कर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग किए जाने का उल्लेख करते हुए मनोज बारोट ने BAVIA नेता क्षितिज ठाकुर से पूछा कि क्या वे इस मांग का समर्थन

करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि BAVIA ने पहले वित्तीय अनियमितताओं और सड़क कार्यों को लेकर सवाल उठाए थे, तो अब सत्ता में रहते हुए उन आरोपों की जांच करवाना उसकी भी जिम्मेदारी है।

बारोट ने कहा कि शहर के कई हिस्सों में आज भी गड्ढों की समस्या बनी हुई है। अमृत योजना 2.0 तथा नालासोपारा जोन-3 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे विकास कार्यों के लिए सड़कों की खुदाई से नागरिकों की परेशानी और बढ़ी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सड़कें खोदना आवश्यक हो सकता है, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़कों की गुणवत्ता के साथ समय पर पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना महानगरपालिका की जिम्मेदारी है।

BAVIA से पूछे पांच सवाल

मनोज बारोट ने BAVIA से सवाल किया कि क्या शहर में गड्ढों की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या प्रशासनिक काल में उठाए गए मुद्दों की जांच की जा रही है? क्या नागरिकों को गड्ढामुक्त और सुरक्षित सड़कें देने का वादा पूरा हुआ है? सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए स्वतंत्र तकनीकी निरीक्षण कराया गया है? और क्या सड़क मरम्मत व विकास कार्यों में जनता के पैसे का पारदर्शी एवं उचित इस्तेमाल हो रहा है?

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इअशक्ष नेताओं ने सड़कें ठीक नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी। अब महानगरपालिका की सत्ता और निर्णय लेने की जिम्मेदारी BAVIA के पास है, इसलिए जनता यह जानना चाहती है कि उस चेतावनी को अब कौन और कब अमल में लाएगा।

भाजपा का रुख स्पष्ट करते हुए बारोट ने कहा कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अधिक महत्वपूर्ण वसई-विरार के नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और गड्ढामुक्त सड़कें उपलब्ध कराना है। उन्होंने मांग की कि महानगरपालिका शहर की प्रमुख एवं अंदरूनी सड़कों का व्यापक सर्वे कराए तथा घटिया, अधूरे या क्षतिग्रस्त सड़क कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच करवाकर उसकी रिपोर्ट जनता के सामने रखे।

अगर चाहें तो इसे मैं और ज्यादा धारदार राजनीतिक अखबारी शैली में 500-600 शब्दों की फुल न्यूज में भी तैयार कर सकता हूँ।

अयोध्या की लोक गायिका संजोली पांडेय ने ठाणे में मराठी और भोजपुरी गीतों से बांधा समा

ठाणे। पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अमरजीत मिश्रा के माध्यम से अभियान संस्था के अंतर्गत मुंबई ठाणे मीरा रोड बसई दीवा डोंबिवली कल्याण आदि जगहों पर श्रावण के महीने में अभियान संस्था के माध्यम से मराठी और भोजपुरी गीतों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी श्रावण महीने मेंउत्तर प्रदेश के अयोध्या से आईं प्रसिद्ध लोक गायिका एवं कजरी क्वीन संजोली पांडेय ने ठाणे के ब्रह्मांड चौक स्थित ज्येष्ठ नागरिक संघ हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रोताओं का दिल जीत लिया। रतन वशिष्ठ नारायण मिश्रा संतोष जायसवाल के नेतृत्व में एवं जयसिंह आनंद दूबे रवि सिंह नागेंद्र मिश्रा अरविंद गिरी सोनम शर्मा आदि गायक दीपक सुहाना छोटे खेसारी सोनू

आदि कलाकार ने प्रस्तुति की इस समारोह में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पुलिस अधिकारी द्वारका भागीरथी विश्वनाथ और पत्रकार श्रद्धा राय को स्त्री शक्ति सम्मान दिया गया।

संजोली पांडेय ने भोजपुरी लोकगीतों के साथ-साथ मराठी गीतों की भी शानदार प्रस्तुति दी। उनकी सुरमयी आवाज और भावपूर्ण गायन पर उपस्थित श्रोता देर तक झूमते और तालियां बजाते रहे। कार्यक्रम में मराठी और भोजपुरी संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार रूप में प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के दौरान संजोली पांडेय ने कहा कि संगीत भाषा और प्रदेश की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने महाराष्ट्र की संस्कृति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए मराठी गीतों की प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। हॉल में उपस्थित श्रोताओं ने उनकी प्रस्तुति की मुक्तकंठ से प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन देश की विविधता में एकता को और अधिक मजबूत करते हैं। संजोली पांडेय की दमदार प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया और कार्यक्रम देर तक उत्साहपूर्ण माहौल में चलता रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/ एसटी मुकदमा किया खारिज

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सरायख्वाजा स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धौरईल के प्रधान संजय कुमार द्वारा उक्त गांव निवासी विंध्यवासिनी मिश्रा और उनके परिजनों के विरुद्ध दर्ज कराया गया फर्जी एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा अब सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी तरह खारिज हो गया। विशेष न्यायालय के फैसले के बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जहां सुनवाई के दौरान 5 अगस्त शीर्ष अदालत ने भी पाया कि विंध्यवासिनी मिश्रा और उनके परिवार के खिलाफ लगाये गये सभी आरोप निराधार, बेबुनियाद और पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ ने निचले कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए केस को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। विंध्यवासिनी मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी मुकदमा खारिज होने के बाद हमको और हमारे परिवार को बहुत बड़ी कानूनी राहत और न्याय मिला है। इस फैसले के बाद परिजनों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर है और उन्होंने इसे सत्य और न्याय की अंतिम जीतर करार दिया।

पीएनजी ज्वेलर्स के सीएमडी डॉ. सौरभ गाडगीळ के अपनी पहली पुस्तक चूजिंग गोल्ड का विमोचन

नवी मुंबई। भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक विरासतों में से एक की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी मध्य तीस की उम्र में संभाली। आज पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सौरभ गाडगीळ अपनी पहली पुस्तक चूजिंग गोल्ड के माध्यम से उस विरासत से जुड़ी अपनी पूरी यात्रा की कहानी साझा कर रहे हैं। इस पुस्तक का राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया गया है। चूजिंग गोल्ड एक बेहद ईमानदार और व्यक्तिगत पुस्तक है। यह उस व्यक्ति की कहानी है, जिसने कम उम्र में भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक विरासतों में से एक को संभाला और अब ४९ वर्ष की आयु में अपनी इस अद्भुत यात्रा को लोगों के सामने ला रहे हैं। यह कहानी दुनिया उन्हें बाहर से जिस तरह

देखती है, उसकी नहीं, बल्कि उस यात्रा की है, जिसे उन्होंने वास्तव में जिया है।

यह पुस्तक उन महत्वपूर्ण क्षणों की कहानी बताती है, जिन्होंने डॉ. गाडगीळ के व्यक्तित्व को आकार दिया; उनके दादा और मां के साथ हुई वे बातचीत, जो जीवनभर उनके साथ रहीं; वे सीख, जिनका वास्तविक अर्थ समय बीतने के साथ समझ में आया; और वे कठिन निर्णय, जिन्होंने उनकी दृढ़ता और विश्वास की परीक्षा ली तथा अंततः उनके सही साबित होने का मार्ग प्रशस्त किया।

पीएनजी ज्वेलर्स की १९४ वर्ष पुरानी विरासत इस यात्रा की पृष्ठभूमि है। लेकिन इस पुस्तक के केंद्र में स्वयं डॉ. गाडगीळ हैं—उनका विकास, उनके निर्णय, उनके संघर्ष और अपने से पहले की विरासत का सम्मान करते हुए अपनी राह स्वयं बनाने का साहस।

पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सौरभ गाडगीळ ने कहा, अपने जीवन के अधिकांश समय में मैं इस यात्रा को जीने में इतना व्यस्त था कि कभी रुककर इसे समझने और परखने का अवसर ही नहीं मिला। जिन सवालों को मैं लगभग तीन दशकों से टालता आया था, उन्हें पूछने के लिए इस पुस्तक को लिखते हुए मैं स्वयं मजबूर हुआ। अपने किन फैसलों पर मुझे वास्तव में गर्व है? कौन-से फैसले आज भी मुझे बेचैन करते हैं? मैंने किन बातों को अपनी समझदारी से सही किया और किन्हें महज अपनी किस्मत से?

पेंगुइन एंटरप्राइज, कस्टम पब्लिशिंग, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के लीड, अनुज दत्ता ने कहा, एक प्रकाशक के रूप में हम हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहते हैं, जो सफलता से आगे भी कुछ प्रस्तुत करती हों। चूजिंग गोल्ड में जिस बात ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया, वह इसकी ईमानदारी है। सौरभ केवल अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करते, बल्कि उन कठिन फैसलों, असफलताओं और संदेह के उन क्षणों पर भी विचार करते हैं, जिन्होंने उनकी यात्रा को आकार दिया। यही बात इस संस्मरण को प्रभावशाली बनाती है। यह केवल व्यवसाय की कहानी नहीं है, बल्कि नेतृत्व और दृढ़ता की एक गहराई से जुड़ी व्यक्तिगत कहानी है। मेरा विश्वास है कि पाठक, चाहे वे उद्यमी हों, कारोबारी नेता हों या अपने करियर के किसी भी पड़ाव पर काम कर रहे पेशेवर, इन पन्नों में अपने लिए कुछ सार्थक अवश्य पाएंगे।

डीएसपी म्यूचुअल फंड ने निवेशकों से की अपील, मल्टी एसेट फंड चुनने के तरीके पर दोबारा विचार करें

मुंबई। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने मल्टी एसेट एलोकेशन श्रेणी के लिए एक नया डिजिटल केंपेन शुरू किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों को हाल में मिले रिटर्न से आगे बढ़कर यह समझ बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है कि इन फंडों की किसी निवेश पोर्टफोलियो में क्या भूमिका होती है।यह अभियान इस आकलन पर आधारित है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंडों में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी जरूर है, लेकिन कई निवेशक अपनी पड़ताल की शुरूआत इस श्रेणी से जुड़ी अलग-अलग उम्मीदों के साथ करते हैं कि आखिर ये फंड किस तरह का लाभ देने के लिए बनाए गए हैं। एम्फी के अनुसार, जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान इक्विटी-आधारित स्कीम में हुए कुल शुद्ध निवेश (नेट इनफ्लो) में मल्टी एसेट एलोकेशन फंडों की हिस्सेदारी 27% रही। यह पिछली तिमाही में 21% और पिछले वर्ष की इसी अवधि में केवल 6% थी। डीएसपी म्यूचुअल फंड में भी इस वर्ष मल्टी एसेट एलोकेशन फंडों में लेन-देन करने वाले निवेशकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले तीन गुना बढ़ गई है। जैसे-जैसे निवेशकों की भागीदारी बढ़ी, डीएसपी ने देखा कि कई निवेशक इस श्रेणी का मूल्यांकन मुख्य रूप से हालिया रिटर्न के आधार पर कर रहे थे। वे पहले यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आखिर होते क्यों हैं।

इससे निवेशकों की अपेक्षाएं इन फंडों की वास्तविक भूमिका से मेल नहीं खातीं। बाजार की परिस्थितियां बदलने पर उनके निराश होने या समय से पहले निवेश से बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। यह समझने के लिए कि निवेशक इस श्रेणी को किस तरह देखते हैं, डीएसपी ने निवेशकों द्वारा किए गए 100 से अधिक सर्च प्रश्नों का विश्लेषण किया।

सवाल अलग-अलग थे, लेकिन व्यापक रूप से वे दो अलग-अलग सोच को दर्शाते थे।

पहला, जिसे डीएसपी ने 'रिटर्न सीकर्स' नाम दिया। मल्टी एसेट एलोकेशन फंडों को मुख्य रूप से हालिया प्रदर्शन के नजरिए से देखता था। उनके सवाल रिटर्न, रैंकिंग और मौजूदा बाजार परिस्थितियों के आधार पर इस श्रेणी के फंड में निवेश करना फायदेमंद है या नहीं जैसे विषयों पर केंद्रित थे। दूसरा समूह, जिसे 'डाइवर्सिफायर्स' कहा गया, इस श्रेणी को अलग नजरिए से देखता था। उनके सवाल पोर्टफोलियो बनाने, उसमें विविधता विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) लाने, एसेट एलोकेशन और अलग-अलग बाजार चक्रों में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किस तरह मदद कर सकते हैं, इस समझ पर आधारित थे।

अर्टिगा कार की टक्कर में नीलगाय की हुई मौत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। रामपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के गंधोंना गांव के पास शुक्रवार को प्रयागराज से जौनपुर की तरफ जा रहे एक अर्टिगा कार और नीलगाय की भीषण टक्कर में निलगाय की मौके पर ही मौत हो गई जबकी कार सवार बाल बाल बच गये। जानकारी के अनुसार उक्त अचानक सड़क पर आई नीलगाय से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आस–पास के लोगों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही जमालपुर चौकी इंचार्ज रामाश्रय कुशवाहा पुलिस बल के साथ पहुंचे और जेसीबी बुलाकर मृत्यु नीलगाय को दफन कराया दुर्घटना कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर जंगली जानवर अचानक सड़क पर आ जाते हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

इंदौर के हार्दिक शर्मा ने 11 वर्ष की आयु में जीता राष्ट्रीय स्वर्ण पदक

प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तरशक्ति)। सामान्य एवं मध्यम वर्ग से आने वाले हार्दिक शर्मा 4 वर्ष की आयु से ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। साढ़े 9 वर्ष की आयु में 2024 के अंत में रायफल शूटिंग क्लब में एडमिशन हुआ साढ़े 10 वर्ष की आयु में नेशनल क्वालीफाई किया और इंटरनेशनल शूटिगं स्पोर्ट्स फेडेरेशन खिलाड़ी बने और 11वर्ष की अल्प आयु में इंटरनेशनल ट्रायल्स में चयनित हुए । हाल ही में जालंधर पंजाब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित 55 राष्ट्रीय 10 मीटर एयर रायफल शूटिंग स्पर्धा अंडर 14 में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक विजेता बने। हार्दिक अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने कोच आनंद शर्मा ईगल शूटिंग क्लब, माता पिता एवं दादा दादी को श्रेय देते हुए बताते है कि रोजाना सुबह 7 बजे पिता संदीप शर्मा हार्दिक को क्लब लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभाते है पिता का मोटीवेशन स्वयं की कड़ी मेहनत कोच आनंद शर्मा का मार्गदर्शन से ही वे आज इस स्थान को प्राप्त कर सके। हार्दिक का सपना अपने देश के लिए ओलिंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त करना है। हार्दिक आगे बताते है कि कई बार डाइट को लेकर पापा जी डांट पड़ती है।

हार्दिक अभी कॉमन वेल्थ 2030 की तैयारी में लगे है। जिस उम्र में अन्य बच्चे मोबाइल गेम्स आदि में लगे होते है हार्दिक शर्मा उस नन्ही उम्र में प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे है । इनका सपना क्रिकेटर बनने का था। लेकिन नसीब ने शूटर बना दिया।

नेपाल पहुंचकर फंसे कैलाश मानसरोवर जा रहे यात्री, भारत सरकार ने जारी की सख्त एडवाइजरी

नई दिल्ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर भारत सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास नेपाल के अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है, ताकि यात्रा के दौरान भारतीय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खास तौर पर दस्तावेजों की कमी, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति और खराब मौसम के कारण आने वाली परेशानियों में दूतावास यात्रियों की मदद कर रहा है। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि विदेश मंत्रालय को ऐसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध मिले, जो निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल पहुंचे थे, लेकिन उनके पास जरूरी चीनी वीजा और प्रवेश परमिट नहीं थे। दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण कई यात्री नेपाल में ही फंस गए। इसी को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने 27 जून 2026 को एडवाइजरी जारी कर भारतीय श्रद्धालुओं से कहा था कि जब तक यात्रा के लिए जरूरी सभी दस्तावेज हासिल न हो जाएं, तब तक भारत से अपनी यात्रा शुरू न करें।

विदेश मंत्रालय ने यात्रियों को खास तौर पर चेताया कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू करना कि रास्ते में या बाद में जरूरी परमिट मिल जाएगा, उन्हें गंभीर परेशानी में डाल सकता है। मंत्रालय के अनुसार, बिना पुष्टि वाले दस्तावेजों के यात्रा शुरू करने से नेपाल में फंसने का जोखिम काफी बढ़ जाता है। सरकार ने श्रद्धालुओं से यह भी कहा है कि वे निजी टूर ऑपरेटर के जरिए यात्रा तय कर रहे हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह पंजीकृत और अधिकृत है। कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि नेपाल में भारतीय तीर्थयात्रियों को खराब

मौसम, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति या दस्तावेजों से जुड़ी परेशानी होने पर भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करता है। संसद में सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुराने रिकॉर्ड की भी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री के अनुसार, कोविड-19 महामारी के बाद 2020 से 2024 तक विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो सकी। इसके बाद चीन की ओर से यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं का नवीनीकरण नहीं होने के कारण भी यात्रा प्रभावित रही। भारत सरकार ने इस मुद्दे को चीन के साथ राजनयिक माध्यमों से लगातार उठाया। इसके बाद 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई। सरकार के अनुसार, 2025 में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा में कुल 688 भारतीय श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यात्रा को दोबारा शुरू कराने के लिए भारत ने चीन के साथ लगातार कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। राज्यसभा में एक अलग लिखित जवाब में कीर्ति वर्धन सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले व्यक्तिगत यात्रियों को सीधी आर्थिक सहायता, सब्सिडी या खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं देती। इसमें वरिष्ठ नागरिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यात्री भी शामिल हैं। यात्रा को सरकार स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित करती है। विदेश मंत्रालय यात्रा को सुचारु बनाने के लिए कई व्यवस्थाओं में समन्वय करता है। इनमें परिवहन, ठहरने की व्यवस्था, भोजन, मेडिकल जांच, गाइड और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारत सरकार चीन तथा उत्तराखंड और सिक्किम की राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय करती है, ताकि यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो सके।

डीएम ने किया श्रीदत्तगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण

बलरामपुर। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने शुक्रवार को विकास खंड श्रीदत्तगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) एवं कार्यालय खंड विकास अधिकारी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं, दवा उपलब्धता तथा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में लेबर रूम स्ट्रेंथनिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित मातृत्व और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अस्पतालों में प्रसूता महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर का भ्रमण करते हुए ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, प्रसूति कक्ष, वार्ड, साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों एवं तीमारदारों से संवाद कर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। दवा वितरण कक्ष में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने, मरीजों को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से दवाएं उपलब्ध कराने तथा अस्पताल परिसर में स्वच्छता एवं अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने कार्यालय खंड विकास अधिकारी, श्रीदत्तगंज का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न शाखाओं का अवलोकन करते हुए अभिलेखों, पंजिकाओं एवं कार्यालयीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अभिलेख अद्यतन रखे जाएं, कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा शासन की विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यालयों में सुव्यवस्थित अभिलेख, नियमित अनुश्रवण एवं जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य से जुड़े कार्यों का त्वरित निस्तारण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने पाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नालासोपारा में प्रदेश सचिव बृजेश प्रजापति का भव्य सम्मान, समाजहित के मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा

-चंदन महाकाल

नालासोपारा। मुंबई के नालासोपारा स्थित श्री नवदुर्गा डेवलपर्स कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव एवं समाजसेवी बृजेश प्रजापति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी बाबा प्रजापति एवं रमेश प्रजापति सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उनका पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मान किया।

सम्मान समारोह के उपरांत आयोजित शिष्टाचार मुलाकात में संजय प्रजापति, नागेंद्र प्रजापति तथा पत्रकार चंदन महाकाल प्रजापति के साथ समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में समाज के विकास, युवाओं के भविष्य, शिक्षा, रोजगार, संगठन की मजबूती तथा सामाजिक एकता को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बृजेश प्रजापति ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। शिक्षा, संगठन और सामाजिक समरसता ही समाज को नई दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया तथा भविष्य में भी ऐसे संवाद और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प दोहराया गया।

सैमसंग गैलेक्सी Z सीरीज की अर्ली डिलीवरी शुरू

मुंबई। सैमसंग ने आज ऐलान किया कि भारत में जिन ग्राहकों ने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z फोल्ड8 अल्ट्रा, गैलेक्सी Z फोल्ड8 और गैलेक्सी फ्लिप8 पहले से बुक किए थे, उन्हें अब जल्दी डिलीवरी दी जा रही है। इन तीनों फोन को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। 22 जुलाई को भारत में लॉन्च होने के सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही 2.71 लाख से ज्यादा प्री-ऑर्डर मिल चुके थे। इसकी तुलना में, पिछली पीढ़ी के गैलेक्सी फोल्ड7 और गैलेक्सी Z फ्लिप7 को इतने ही प्री-ऑर्डर तक पहुंचने में 15 दिन लगे थे। इससे साफ पता चलता है कि फोल्डेबल तकनीक अब आम लोगों तक और तेजी से पहुंच रही है। सैमसंग गैलेक्सी Z सीरीज के लिए अभी प्री-ऑर्डर करने पर ग्राहकों को 10,000 रुपये का अपग्रेड ऑफर, या 9,000 रुपये तक का बैंक/यूपीआई कैशबैक, या 0% डाउन पेमेंट के साथ 30 महीने का नो-कॉस्ट ईएमआई मिलेगा।

जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग की मुहिम तेज, तीन स्थानों पर लगे स्वास्थ्य शिविर, एक टाइफाइड मरीज मिला

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। अर्बन जौनपुर के चाचकपुर में डॉ. प्रेम चंद्र, उमरपुर में डॉ. नाज़िया परवीन तथा ब्लॉक जलालपुर के त्रिलोचन में डॉ. शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में शिविर आयोजित हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चाचकपुर में 18 तथा उमरपुर में 21 लोगों की मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड की जांच की गई, जिसमें सभी रिपोर्ट नकारात्मक रहीं। वहीं त्रिलोचन में 27 लोगों की जांच के दौरान एक व्यक्ति टाइफाइड पॉजिटिव मिला, जिसे तत्काल दवा उपलब्ध कराकर उपचार शुरू करा दिया गया। शिविर के दौरान चाचकपुर और उमरपुर में जलभराव वाले क्षेत्रों में एंटी-लार्वा रसायन का छिड़काव, ब्रीडिंग सोर्स सर्वे, सोर्स रिडक्शन, आशा कार्यकताओं द्वारा फीवर सर्वे, डेंगू एवं मलेरिया से बचाव संबंधी पोस्टर चस्पा करने, पंपलेट वितरण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों और आसपास साफ-सफाई रखें, जलभराव न होने दें, कूलर, गमले और फ्रिज की ट्रे का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें तथा मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। साथ ही बुखार आने पर बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निःशुल्क जांच और उपचार कराने की सलाह दी गई। इस दौरान सहायक मलेरिया अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा, सुजीत कुमार प्रभाकर, फाइलेरिया निरीक्षक अभिषेक सोनकर, दीपक सिंह तथा क्षेत्रीय आशा कार्यकताओं सहित स्वास्थ्य विभाग का अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग की मुहिम तेज, तीन स्थानों पर लगे स्वास्थ्य शिविर, एक टाइफाइड मरीज मिला

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। अर्बन जौनपुर के चाचकपुर में डॉ. प्रेम चंद्र, उमरपुर में डॉ. नाज़िया परवीन तथा ब्लॉक जलालपुर के त्रिलोचन में डॉ. शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में शिविर आयोजित हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चाचकपुर में 18 तथा उमरपुर में 21 लोगों की मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड की जांच की गई, जिसमें सभी रिपोर्ट नकारात्मक रहीं। वहीं त्रिलोचन में 27 लोगों की जांच के दौरान एक व्यक्ति टाइफाइड पॉजिटिव मिला, जिसे तत्काल दवा उपलब्ध कराकर उपचार शुरू करा दिया गया। शिविर के दौरान चाचकपुर और उमरपुर में जलभराव वाले क्षेत्रों में एंटी-लार्वा रसायन का छिड़काव, ब्रीडिंग सोर्स सर्वे, सोर्स रिडक्शन, आशा कार्यकताओं द्वारा फीवर सर्वे, डेंगू एवं मलेरिया से बचाव संबंधी पोस्टर चस्पा करने, पंपलेट वितरण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों और आसपास साफ-सफाई रखें, जलभराव न होने दें, कूलर, गमले और फ्रिज की ट्रे का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें तथा मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। साथ ही बुखार आने पर बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निःशुल्क जांच और उपचार कराने की सलाह दी गई। इस दौरान सहायक मलेरिया अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा, सुजीत कुमार प्रभाकर, फाइलेरिया निरीक्षक अभिषेक सोनकर, दीपक सिंह तथा क्षेत्रीय आशा कार्यकताओं सहित स्वास्थ्य विभाग का अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

स्टैण्डर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड नतीजे दर्ज किए

मुंबई। भारत की प्रमुख हाई-प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एसइटीएल) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए एक और रिकॉर्ड-तोड़ तिमाही नतीजों की घोषणा की है। साथ ही, कंपनी ने दो अहम रणनीतिक कदम भी उठाए हैं जो कंपनी की विकास की दिशा को नई शक्ल देंगे। एसइटीएल की कुल आय 252.2 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल के मुकाबले 41.5% ज्यादा है। एबिटडा 44.1 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 27.3% की बढ़ोतरी हुई और मार्जिन 17.5% पर बना रहा। टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26.5% बढ़कर 36 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टैक्स के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.6% बढ़कर 26.7 करोड़ रुपये रहा, जिससे पैट मार्जिन 10.6% हो गया। खास बात यह है कि यह ग्रोथ तब हासिल हुई जब कंपनी अपने नए ग्रोथ प्लेटफॉर्म में भारी निवेश कर रही थी – यह कंपनी के मुख्य कारोबार की मजबूती और कैश बनाने की क्षमता का संकेत है। एमडी नागेश्वर राव कंडुला ने इस तिमाही के नतीजों को किसी एक बार की कामयाबी के बजाय लगातार और दोहराए जा सकने वाले अच्छे प्रदर्शन का सबूत बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसइटीएल ₹भारत का हाई-प्रिसिजन इंजीनियरिंग पावरहाउस₹ बन रहा है। उन्होंने जीस्केल के निर्माण और जीएल हक्कों के साथ साझेदारी, दोनों में टीम के शानदार काम का श्रेय दिया। साथ ही, उन्होंने अनुशासित तरीके से पूंजी लगाने, टेक्नोलॉजी पर आधारित साझेदारियां करने और ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों व साझेदारों के लिए लंबे समय तक वैल्यू बनाने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। इस तिमाही की सबसे बड़ी रणनीतिक खबर एसइटीएल का भारत के तेजी से बढ़ते एआई डेटासेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में कदम रखना है। यह कदम जीस्केल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेडमें 51% तक इक्विटी के प्रस्तावित अधिग्रहण के जरिए उठाया गया है। इस कदम से कंपनी के लिए विकास का एक दूसरा जरिया तैयार होगा, जिसे एक इंटीग्रेटेड डेटासेंटर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये के सेल्फ-फंडेड कैपिटल प्रोग्राम का समर्थन प्राप्त है।

एसइटीएल ने जापान की जीएल हक्कों कंपनी लिमिटेड के साथ अपने लगभग दस साल पुराने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और मजबूत किया है। कंपनी ने शुरूआती तौर पर 19.19% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए रू71.5 करोड़ का निवेश किया है, साथ ही उसे पहले से तय वैल्यूएशन पर तीन साल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51.07% करने का अधिकार भी मिला है। 1955 में स्थापित जीएल हक्कों के पास ग्लास-लाइनिंग का 70 से ज्यादा सालों का अनुभव है और उसने दुनिया भर में 20,000 से ज्यादा यूनिट्स की सप्लाई की है। इस पार्टनरशिप से एसइटीएल को खास टेक्नोलॉजी – जैसे कंडक्टिविटी ग्लास, ग्लास-लाइन्ड शेल-एंड-ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स और सेमीकंडक्टर-ग्रेड प्रोसेस इक्विपमेंट – तक पहुंच मिलेगी, साथ ही एसइटीएल का कुल एड्रेसेबल मार्केट बढ़कर 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। इस विस्तार के लिए फंड जुटाने के मकसद से, बोर्ड ने लगभग 136.5 करोड़ रुपये के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को मंजूरी दी। इसमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स एजीआई ग्रुप होल्डिंग्स इंक. (जापान) और मोनोफ्लस प्राइवेट लिमिटेड (सिंगापुर) से कैश के तौर पर 71.5 करोड़ रुपये, और जीस्केल में हिस्सेदारी के बदले ट्रुप्लस्को इंडिया एलएलपी के साथ शेयर स्वैप के जरिए लगभग 65 करोड़ रुपये शामिल हैं।

जर्मनी में शासन-भू-राजनीति पर अंतरराष्ट्रीय समर स्कूल के लिए आलोक तिवारी का चयन

कल्याण। गुरुग्राम ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, हरियाणा में प्रोग्राम मैनेजर (इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी) के पद पर कार्यरत आलोक वीरेंद्र तिवारी का चयन जर्मनी में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय समर स्कूल के लिए हुआ है। 3 से 15 अगस्त, 2026 तक जर्मनी के पासाउ और म्यूनिख में आयोजित होने वाले इस 13 दिवसीय कार्यक्रम में वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पासाउ विश्वविद्यालय की ओर से हन्स सीडेल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस प्रथम अंतरराष्ट्रीय समर स्कूल में दुनिया के 14 देशों के 25 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। इनमें भारत से आलोक वीरेंद्र तिवारी भी शामिल हैं।

सुशासन और बदलती भू-राजनीति पर होगा मंथन

'विकेंद्रीकरण, सुशासन और भू-राजनीतिक बदलाव' विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे परिवर्तनों का विकेंद्रीकरण, राज्य की क्षमता और स्थानीय शासन व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के दौरान तुलनात्मक संघवाद, उप-राष्ट्रीय कूटनीति, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और बदलते वैश्विक परिदृश्य में राज्यों की लचीलापन क्षमता जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को बवेरियन संसद में संवाद, नीति-निर्माण से जुड़े सिमुलेशन अभ्यास और व्यावहारिक प्रशिक्षण का भी अवसर मिलेगा। चयन पर आलोक वीरेंद्र तिवारी ने कहा, इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं शासन और उप-राष्ट्रीय कूटनीति पर भारतीय दृष्टिकोण साझा करने के साथ-साथ विभिन्न देशों के अनुभवों से सीखकर लौटने के लिए उत्साहित हूं। आलोक ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। इसके अलावा उनके पास लोक नीति (पब्लिक पॉलिसी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। उनके चयन को शिक्षा और लोक नीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

ब्रिजस्टोन इंडिया ने भारत में मोबिलिटी और विकास को गति देने के 30 साल के सफर का मनाया जश्न

मुंबई। जापान के ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन की ग्रुप कंपनी ब्रिजस्टोन इंडिया ने 30 साल पहले भारत में परिचालन की शुरूआत की थी। ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन ने अपनी स्थापना के समय से ही विदेश में अपने कारोबार को विस्तार देने पर फोकस किया है। इसकी शुरूआत एशियाई बाजार में कदम रखने से हुई थी। आज के समय में कंपनी दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में हाई-क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और स्थानीयता के अनुरूप कारोबारी इकाइयों को स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है। ब्रिजस्टोन इंडिया ने नई दिल्ली में प्रमुख भागीदारों के साथ मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कंपनी ने अपने उन पार्टनर्स के योगदान को सम्मानित किया, जिनका सहयोग कंपनी के विकास के सफर में महत्वपूर्ण रहा है। इस आयोजन में एंबेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी टु इंडिया एंड द किंगडम ऑफ भूटान (भारत एवं भूटान में जापान के असाधारण एवं पूर्णाधिकार प्राप्त राजदूत) महामहिम श्री ओनो केइची मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर अग्रणी ऑटोमोटिव मैन्यूफैक्चरर्स, सप्लायर पार्टनर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और प्रतिष्ठित सरकारी प्रतिनिधि एक मंच पर आए। सभी संबंधित लोगों को लंबी साझेदारी और ब्रिजस्टोन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भारत के प्रति तीन दशक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए इस कार्यक्रम ने इनोवेशन, सेफ्टी, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और ग्राहकों को केंद्र में रखने वाले मोबिलिटी सॉल्यूशंस देने पर ब्रिजस्टोन इंडिया के फोकस को सबके सामने रखा। इस कार्यक्रम ने स्टेकहोल्डर्स के मजबूत इकोसिस्टम का जश्न मनाने का भी मौका दिया, जिनके योगदान ने कंपनी के विकास में मदद की है और इसे भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर के विकास में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया है। भारत में ब्रिजस्टोन ने 1996 में परिचालन शुरू करते हुए अपने सफर की शुरूआत की थी। इसके बाद वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर स्थित अपने पहले संयंत्र में कंपनी ने लोकल मैन्यूफैक्चरिंग (स्थानीय विनिर्माण) की शुरूआत की।

टाटा मोटर्स ने लॉन्च की नई 'नेक्सॉन कैमो'

मुंबई। भारत की अग्रणी यात्री वाहन कंपनियों में से एक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) ने आज नेक्सॉन कैमो लॉन्च करने की घोषणा की। यह लॉन्च नेक्सॉन के 10 साल पूरे होने और 11 लाख से ज्यादा ग्राहकों के भरोसे का जश्न मनाने के मौके पर हुआ है। इसकी शुरूआती एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 9.99 लाख रुपये रखी गई है। नेक्सॉन कैमो दो विशेष प्रीमियम रंगों, मुन्नार मिस्ट और कूर्ग क्लाउड में उपलब्ध होगी। यह नया संस्करण आकर्षक डिजाइन के साथ उन्नत तकनीक का भी बेहतरीन मेल है। इसमें अल्ट्रा व्यू ट्विन एचडी डिजिटल कॉकपिट दिया गया है, जिसमें 31.24 सेमी (12.3 इंच) का हरमनट्ठ इंफोटेनमेंट सिस्टम और 26.03 सेमी (10.25 इंच) का हरमनट्ठ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इन-बिल्ट नेविगेशन की सुविधा है, जबकि 360ट कैमरा सराउंड व्यू सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड डैशकैम रिकॉर्डर भी दिया गया है। इसके अलावा, नेक्सॉन कैमो में प्रीमियम आराम, सुरक्षा और स्मार्ट तकनीक से जुड़े कई फीचर्स शामिल हैं। इनमें एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), वॉइस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स और जेबीएल ऑडियो सिस्टम प्रमुख हैं। नई नेक्सॉन कैमो पेट्रोल, डीजल और आईसीएनजी, तीनों पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगी। साथ ही ग्राहकों को अलग-अलग ट्रांसमिशन विकल्प भी मिलेंगे, जिससे यह हर तरह के एसयूवी खरीदार के लिए एक अलग और आकर्षक विकल्प बनकर सामने आती है। वर्षों के दौरान टाटा नेक्सॉन ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों और उम्मीदों के हिसाब से लगातार खुद को बेहतर बनाया है, और भारत के सबसे सफल और भरोसेमंद एसयूवी ब्रांड्स में अपनी जगह बनाई है। इसने सुरक्षा, अत्याधुनिक तकनीक और टर्बोचार्ज्ड परफॉर्मेंस को आम ग्राहकों तक पहुंचाया है और कई पावरट्रेन विकल्प भी दिए हैं। इस तरह नेक्सॉन ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों की उम्मीदों को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और साथ ही नई सोच व ग्राहकों के भरोसे की मजबूत विरासत भी बनाई है। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पेश की गई नेक्सॉन कैमो इसी सोच को आगे बढ़ाती है। यह एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग, उन्नत तकनीक और नए प्रीमियम रंगों को नेक्सॉन की सुरक्षा, दमदार प्रदर्शन और हर स्थिति में काम आने जैसी स्थापित खूबियों के साथ जोड़ती है। नई नेक्सॉन कैमो पेट्रोल, डीजल और आईसीएनजी, तीनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी।

बीएचयू के एक कार्यक्रम में उठे विचारों ने स्त्री स्वतंत्रता, भक्ति साहित्य और सामाजिक न्याय पर नई चर्चा छेड़ी

-सुरेश गांधी

वाराणसी. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष राय ने जब कहा कि भक्ति कवयित्रियाँ साहस के साथ पितृसत्ता का प्रतिरोध रचती हैं, तो यह टिप्पणी केवल अतीत की चर्चा नहीं रही; उसने वर्तमान समाज के सामने भी कई प्रश्न खड़े कर दिए। कार्यक्रम को एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन उसमें उठे विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

राय ने दक्षिण भारत की संत कवयित्रियों अंडाल और अक्का महादेवी के उदाहरणों के माध्यम से बताया कि मध्यकालीन समाज में स्त्रियों और शूद्रों पर धार्मिक प्रतिबंध थे। जब संस्थागत धर्म ने उनके लिए रास्ते बंद किए, तब उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपनी भाषा, अपने गीत और अपनी अनुभूति को माध्यम बनाया। यह भक्ति केवल आत्मिक साधना नहीं थी; यह सामाजिक अवरोधों के विरुद्ध सांस्कृतिक प्रतिरोध भी थी।

अक्का महादेवी के प्रसंग को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पति और स्वतंत्रता के बीच स्वतंत्रता को चुना। इसी तरह अंडाल की कविताओं में प्रेम निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि अधिकारपूर्वक संवाद का रूप लेता है। यह स्वर उत्तर भारतीय भक्ति परंपरा से भिन्न दिखाई देता है और इसी कारण गंभीर अध्ययन की मांग करता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साहित्यकार अवधेश प्रधान ने कहा कि भक्ति साहित्य भारतीय सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण आधार है। अलवार और नायनार परंपराएं बताती हैं कि उत्तर और

दक्षिण भारत परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि गहरे सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। अंडाल की कल्पना में वृंदावन और दक्षिण की धरती एक ही आध्यात्मिक भूगोल का हिस्सा बन जाते हैं।

चर्चा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी रहा कि इतिहास में अनेक प्रतिभाशाली स्त्रियों की स्मृतियां दबा दी गईं। यह प्रश्न आज भी बना हुआ है कि साहित्यिक परंपराओं में स्त्री स्वर को कितनी जगह मिली है और उसकी व्याख्या किस दृष्टि से की गई है।

बीएचयू में हुई यह चर्चा दरअसल एक बड़े सांस्कृतिक विमर्श की ओर संकेत करती है। आज जब स्त्री अधिकार, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नए सिरे से बहस चल रही है, तब अंडाल और अक्का महादेवी जैसी कवयित्रियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं रह जातीं; वे साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्र चेतना की ऐतिहासिक आवाज बनकर सामने आती हैं।

काशी की इस बहस का महत्व इसलिए भी है कि उसने भक्ति साहित्य को केवल पूजा-पाठ के दायरे से बाहर निकालकर सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के प्रश्नों से जोड़ दिया है। यही वह बिंदु है जहां साहित्य अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान का हस्तक्षेप बन जाता है। सुभाष राय का जन्म जनवरी 1957 में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के बड़ागांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय के के.एम.आई. संस्थान से हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर तथा विधि की पढ़ाई पूरी की। संत कवि दादूदयाल के साहित्य पर उन्होंने पीएचडी की।

आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और जेल यात्रा के बाद वे पिछले चार दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित दैनिक समाचारपत्रों में शीर्ष पदों पर कार्य करने के पश्चात वर्तमान में लखनऊ से प्रकाशित जनसंदेश टाइम्स के प्रधान संपादक हैं।

उनकी प्रमुख कृतियों में सलीब पर सच, मूर्तियों के जंगल में, जाग मछन्दर जाग और अंधेरे के पार शामिल हैं। रजा न्यास की फेलोशिप पर दिगम्बर विद्रोहिणी अक्क महादेवी तथा आ आत्मसंभवा आंडाल प्रकाशित हुईं। उन्हें नई धारा रचना सम्मान, माटी रतन सम्मान, देवेंद्र कुमार बंगाली स्मृति कविता सम्मान, स्पंदन कृति आलोचना सम्मान और प्रो. शुकदेव स्मृति सम्मान सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। वर्तमान निवास गोमतीनगर, लखनऊ है।

18 साल पुराने हत्या के मामले में आया फैसला, दोषी को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माना

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। करीब 18 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) जौनपुर ने थाना नेवढ़िया क्षेत्र के वर्ष 2008 में दर्ज हत्या के मुकदमे में अभियुक्त प्रेमचन्द्र उर्फ पप्पू सरोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया कि यदि अभियुक्त निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 2008 में थाना नेवढ़िया में दर्ज हत्या के मुकदमे से संबंधित था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय के इस फैसले को लंबे समय से लंबित मामले में न्याय मिलने के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह संदेश भी गया है कि गंभीर अपराधों में कानून की प्रक्रिया भले समय ले, लेकिन दोषियों को अंततः सजा मिलती है।